लखनऊ

शुक्रवार, 3 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 219

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"डर को हराकर शुरू करो और मेहनत को अपनाकर आगे बढ़ो यही असली सफलता का रास्ता है।"

TODAY WEATHER

DAY 34° Hi

NIGHT 21° Low

संक्षेप

पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के बीच भारत पूरी तरह अलर्ट, Hormuz पर UK की बैठक में विदेश सचिव ने लिया हिस्सा

वॉशिंगटन, एजेंसी। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता जैसे विषय प्रमुख रूप से सामने आए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सबसे पहले लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस समय लगभग छह सौ भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल लेबनान में तैनात हैं। भारत कई दशकों से शांति अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहा है और वह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा सैनिक योगदान देने वाला देश है। उन्होंने हाल ही में इस मिशन पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इन हमलों में कई सैनिकों की जान गई है, जो अत्यंत दुखद है। भारत ने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और शांति सैनिकों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पड़ोसी देशों को किये जा रहे ऊर्जा सहयोग के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत वर्ष 2007 से बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता आ रहा है।

116 करोड़ रुपये के चालान, अस्तित्वहीन संस्थाओं के सुनियोजित नेटवर्क का खुलासा

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इटानगर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने अमित ट्रेडर्स और अन्य संस्थाओं से जुड़े फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट के संबंध में युपिया स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में अभियोग दायर किया है। यह अभियोग पीएमएलए की धारा 44 और 45 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए दायर किया गया है। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट के जरिए 116 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाए गए। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए अस्तित्वहीन संस्थाओं का सुनियोजित नेटवर्क तैयार किया गया। इसका उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी कर फर्जी आयकर (आईटीसी) उत्पन्न करना था। ईडी के मुताबिक, आरोपियों ने फर्जी आईटीसी को आगे बढ़ाया। यह भी पता चला है कि राम एंटरप्राइजेज कंपनी लगभग 116 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी उत्पन्न करने में प्रमुख भूमिका निभा रही थी। बाद में इसे अमित ट्रेडर्स, नेमचंद सिंह ट्रेडर्स, योगेश ट्रेडर्स, पारस ट्रेडर्स, श्री महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज और टेक्नोफैब इंटरनेशनल सहित कई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया। अमित ट्रेडर्स एक अस्तित्वहीन संस्था है, जिसे फर्जी आईटीसी का लाभ उठाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था।

पीएम मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह में बताया भविष्य का विजन, विकसित भारत-एआई पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्मयोगी साधना सप्ताह के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधारों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस दौर में दुनिया और व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। भारत भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकारी कामकाज और प्रशासन से जुड़े लोग खुद को समय के हिसाब से अपडेट रखें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्मयोगी साधना सप्ताह इसी बदलाव की एक जरूरी कड़ी है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सरकारी सेवा में लगे सभी लोगों को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके प्रयासों की सराहना की।

सरकार नागरिक देवो भव के सिद्धांत पर कर रही काम

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान सरकार 'नागरिक देवो भव' के सिद्धांत पर काम कर रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को अधिक सक्षम और जनता के प्रति संवेदनशील बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए। आजादी के बाद से देश में कई संस्थाएं बनीं, लेकिन अब ऐसी संस्था की जरूरत थी जो सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर काम करे।

2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने समय में सरकारी अधिकारी बनने पर केवल अधिकारों की बात होती थी। लेकिन आज के दौर में सरकार का पूरा जोर कर्तव्य पर है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हमें आर्थिक विकास को तेज करना होगा और एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करनी होगी। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से हम सक्षम टीम तैयार कर रहे हैं जो देश के विकास में अपनी ताकत झोंक सके।

प्रधानमंत्री ने शासन और प्रशासन में तकनीक के महत्व पर विशेष चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में तकनीक के बिना शासन चलाना संभव नहीं है। अर्थव्यवस्था से लेकर सरकारी योजनाओं के वितरण तक में तकनीकी क्रांति दिख रही है। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये बदलाव और भी तेजी से होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारी सेवा में तकनीक का उपयोग करना अब अनिवार्य हिस्सा बन गया है। इससे हम पिछड़ी और प्रगतिशील व्यवस्था के बीच के अंतर को खत्म कर सकेंगे।

क्या है साधना सप्ताह का उद्देश्य?

क्षमता निर्माण आयोग ने 2 से 8 अप्रैल 2026 तक साधना सप्ताह का आयोजन किया है। यह अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है। यह आयोजन मिशन कर्मयोगी के पांच साल पूरे होने और क्षमता निर्माण आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। इसका मकसद प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करना और राष्ट्रीय उन्नति के लिए मानवीय योग्यता को बढ़ाना है।

इस पहल में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 250 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हो रहे हैं। देश भर के प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिकारियों को जरूरी ट्रेनिंग देना और उनकी स्किल को बेहतर बनाना है।

जिस मंत्रालय से पूछा गया सवाल उसके मंत्री ही संसद में नहीं थे...लोकसभा स्पीकर ने कहा- दोबारा ऐसा नहीं होना

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को सदन में कुछ सदस्यों के देर तक बातचीत करने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा उन्होंने एक मंत्री के विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाने के दौरान सदन में मौजूद ना होने पर गुस्सा जाहिर किया। प्रश्नकाल के दौरान एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाना था। यह सवाल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) से जुड़ा था। लेकिन उस समय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सदन में मौजूद नहीं थे। उनके राज्य मंत्री भी अनुपस्थित थे। जिसपर सदन अध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगाई।

इस पर अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि वे इस मामले को ध्यान में लें और आगे से ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करें। अध्यक्ष ने पूछा कि एमएसएमई के राज्य मंत्री कौन हैं? राज्य मंत्री के भी अनुपस्थित रहने का संज्ञान लेने के बाद बिरला ने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले को ध्यान में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।

शून्यकाल शुरू होने पर अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कई सदस्यों और मंत्रियों को खड़े होकर लंबी बातचीत करते देखा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जरूरत होने पर ही एक-दो मिनट बात कर सकते हैं। लंबी बातचीत नहीं करनी चाहिए। बिरला ने चेतावनी दी कि आगे से वह ऐसा करने वालों के नाम लिए जाएंगे

इससे पहले प्रश्नकाल में अध्यक्ष ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टोका। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव आसन (स्पीकर की तरफ) की तरफ पीठ करके कई मिनट से दूसरे सदस्य से बात कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा, "आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।"

मालदा में जजों को बनाया बंधक, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, सीबीआई या एनआईए जांच कराने की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 काफी करीब है। ऐसे में बंगाल में SIR हटाने के विरोध में यहां प्रदर्शन इतना भड़क गया कि मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे तक घेर लिया गया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालती हैं और इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित मालदा के एक गांव में हुए प्रदर्शन के दौरान यह घटना सामने आई, जहां प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को घेर लिया और उन्हें वहां से जाने नहीं दिया।

पश्चिम बंगाल SIR मामले को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने कहा कि मुझे अभी टेलीग्राफ से एक रिपोर्ट मिली है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि मैं इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। लेकिन हमें सुबह 2 बजे से ही रिपोर्ट मिल रही थी। यहां शाम 5 बजे उन्होंने अधिकारियों का घेराव किया और रात 11 बजे तक वहां कोई नहीं था। सिब्बल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि ज्यादातर अधिकारियों का तबादला राज्य से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हुए विरोध प्रदर्शन का गंभीर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा गांव में हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट का संदर्भ लिया।

'ऐसा ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा'

मालदा जिले में एसआईआर ड्यूटी के दौरान न्यायाधीशों पर हुए हमले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा कि हमने ऐसा ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा। मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल से कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में आप सभी राजनीतिक भाषा बोलते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमने ऐसा ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को बुलाने का निर्देश दिया।

अब राष्ट्रपति तक पहुंचा आईएएस अफसर रिंकू राही का मामला, कांग्रेस ने कर दी ये बड़ी मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही के इस्तीफे को लेकर अब राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप करने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है, 'एक ईमानदार दलित अधिकारी को व्यवस्था में काम नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से अधिकारी ने नैतिक आधार पर अपना तकनीकी इस्तीफा सौंपा है।' पार्टी ने मांग की है कि इस इस्तीफे को स्वीकार न किया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार को उन्हें उचित काम देने का निर्देश दिया जाए। रिंकू सिंह राही वर्तमान में लखनऊ के राजस्व परिषद में तैनात हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आईएएस सेवा से तकनीकी इस्तीफा देने की अनुमति मांगी है।

असम में कांग्रेस की रैली, राहुल ने संविधान का जिक्र कर लिए अदाणी-पतंजलि के नाम

गुवाहाटी, एजेंसी। लोकसभा विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए असम पहुंचे है। इस दौरान उन्होंने कार्बी आंगलोंग में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, असम फूलों का एक गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति और विचारधाराओं के लोग साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच है, हिंदुस्तान की जनता के हाथ में असली ताकत हो, देश को चलाने में हर वर्ग को भागीदारी मिले। दूसरी तरफ भाजपा की विचारधारा है कि असम को दिल्ली से चलाया जाए। राहुल के अनुसार, यही लड़ाई चल रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि हमने अनुच्छेद 244ए इसलिए लागू किया क्योंकि हमारा मानना है कि फैसले स्थानीय स्तर पर होने चाहिए। ये फैसले गुवाहाटी या दिल्ली से नहीं, बल्कि यहीं आपके नेता और परिषदें लें। यही हमारे और उनके बीच का फर्क है। आपको लगता है कि फैसलों का सिलसिला गुवाहाटी से शुरू होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी जमीन छीनकर अडानी को अंबानी और पतंजलि बीघा जमीन दे दी गई। हजारों बीघा जमीन दूसरी बड़ी कंपनियों को भी मिली है। आपको यह समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते पर दस्तखत किए। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां इसकी बात क्यों कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि दबाव कहां से आ रहा है। उस समझौते में भारत की खेती-किसानी के रास्ते इस तरह खोले गए हैं, जिसका बुरा असर हमारे किसानों पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज अगर भारत रूस, ईरान या इराक जैसे देशों से तेल खरीदना चाहता है, तो उसे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती है। हम बिना पूछे तेल नहीं खरीद सकते। नरेंद्र मोदी ने भारत का डेटा डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है। अब वे अपनी मर्जी से इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे जमा रख सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने वादा किया है कि भारत हर साल अमेरिकी कंपनियों से 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदेगा। इससे हमारे छोटे कारोबारों और उद्योगों को भारी नुकसान होगा। भारत ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला।

बिना डर वोट दें, टीएमसी को उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक दें, ममता के गढ़ भवानीपुर में गरजे अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कोलकाता में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हर किसी को बिना किसी डर के मतदान करना चाहिए ताकि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके और उसे बंगाल की खाड़ी में बहा दिया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार किसी को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी गुंडा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को नहीं रोक सकता। अमित शाह ने कोलकाता में एक चुनावी रैली में कहा कि इस बार किसी को डरने की जरूरत नहीं है; कोई गुंडा बंगाल के मतदाताओं को नहीं रोक सकता। हर किसी को बिना किसी डर के मतदान करना चाहिए ताकि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके और उसे बंगाल की खाड़ी में बहा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा। लेकिन आप भाबनीपुर में बदलाव चाहते हैं या नहीं? मैं यहां अपने उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के लिए आपके वोटों की अपील करने आया हूं। बंगाल में लगभग हर दिन बम हमले और गोलीबारी की खबरों का हवाला देते हुए अमित शाह ने कहा कि न केवल बंगाल में बल्कि ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भाबनीपुर में भी बदलाव आएगा। गौरतलब है कि अमित शाह ने गुरुवार को भाबनीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के नामांकन दाखिल करने के कार्यक्रम में भाग लिया और उनके साथ रोड शो किया। रोड शो भाबनीपुर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए सर्वे भवन पर समाप्त हुआ, जहां अधिकारी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक फासीवाद जैसा वातावरण, मैं असहाय महसूस कर रही... हेमा मालिनी का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र

नई दिल्ली, एजेंसी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी और दुख व प्रकट किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में कलाकारों को परफॉर्म करने से रोका जा रहा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक दुनिया इन दिनों एक अजीब बेचैनी से गुजर रही है। रंगमंच, संगीत और कला से जुड़े लोग, जो समाज को संवेदनशीलता और सौंदर्य का संदेश देते हैं, खुद असुरक्षा और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। इसी दर्द और चिंता को शब्द देते हुए, प्रसिद्ध अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी जी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा।

उन्होंने अपने पत्र में बताया कि पश्चिम बंगाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जा रही है। कलाकारों को मंच तक पहुंचने से रोका जा रहा है और जो कार्यक्रम तय भी होते हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती। इससे न सिर्फ कलाकारों का मनोबल टूटता है, बल्कि समाज के सांस्कृतिक ताने-बाने पर भी असर पड़ता है। कला हमेशा से लोगों को जोड़ने का माध्यम रही है, भाषा, धर्म और राजनीति से परे है, लेकिन जब कलाकार ही भय और असुरक्षा में जीने लगें, तो यह केवल एक राज्य का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक आत्मा पर सवाल खड़ा करता है।

पत्र के मुख्य प्वाइंट क्या हैं?

आपको गहरे दुःख, चिंता और असहायता की भावना के साथ पत्र लिख रही हूं।

केवल एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि जिसने अपना पूरा जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर शास्त्रीय नृत्य के संरक्षण, प्रचार और अभ्यास के लिए समर्पित किया है। यह मेरा बचपन से ही जुनून रहा है और ईश्वर की कृपा से मुझे वर्षों तक इसे आगे बढ़ाने के अनेक अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरे लिए संस्कृति हमेशा एक पवित्र कर्तव्य रही है। इसी कारण यह अत्यंत पीड़ादायक है कि पश्चिम बंगाल में एक बढ़ता हुआ सांस्कृतिक फासीवाद जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है। यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक रूप से कला, साहित्य और परिष्कृत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का केंद्र रहा है। विशेषकर कोलकाता लंबे समय से बौद्धिक गहराई और कलात्मक उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है।

मैंने हमेशा पश्चिम बंगाल और कोलकाता के लोगों में संस्कृति के प्रति गहरी सराहना देखी है। हालांकि, हाल के सालों में हुए घटनाक्रमों ने देशभर के कलाकारों और सांस्कृतिक साधकों को गहरी पीड़ा दी है।

हाल में हुए दुखद घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि 15 मार्च को, हम कोलकाता के प्रतिष्ठित धोनो धान्यो ऑडिटोरियम में द्रौपदी डांस ड्रामा प्रस्तुत करने वाले थे। यह कार्यक्रम अंतिम समय में अचानक रद्द कर दिया गया और इसके लिए बार-बार बदलते और असंगत कारण बताए गए, जिनमें लॉजिस्टिक समस्याएं और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया।

AAP ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाया, कहा- बोलने के लिए न दिया जाए समय

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (AAP) ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उप नेता के पद से हटा दिया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र देकर यह जानकारी दी है। इसके अलावा AAP ने यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने के लिए समय न दिया जाए। अब पार्टी के राज्यसभा में नए उप नेता डॉ। अशोक मित्तल होंगे, जो पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। AAP ने यह पत्र राज्यसभा सचिवालय को भेज दिया है।

राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच कुछ मतभेद या दूरी की खबरें और अटकलें लंबे समय से चल रही हैं। AAP के इस कदम से उनके बीच चल रहे मतभेद पर मुहर लगती दिख रही है। लेकिन आधिकारिक रूप से विवाद या पार्टी से अलग होने जैसा कोई बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया है।

पार्टी के अभी राज्यसभा में 10 सदस्य हैं, जिनमें से सात पंजाब से और तीन दिल्ली से हैं। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही इससे जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2012 में अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली लोकपाल बिल पर काम करते हुए की थी। पार्टी में उनका कद तेजी से बढ़ा, वे राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और AAP की 2015 के दिल्ली चुनावों में जीत के बाद पार्टी के सबसे कम उम्र के कोषाध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली से लड़ा, लेकिन रमेश बिधूड़ी से हार गए। इसके बाद उन्होंने 2020 में राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता। 2022 में राघव चड्ढा 33 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बने और तब से उन्होंने मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नेताओं के साथ काम करते हुए, AAP के संसदीय और संगठनात्मक मामलों में अहम भूमिका निभाई है।

'हैलो...आपकी प्रोफाइल 20 लोगों ने पसंद की, बात करेंगे', वैवाहिक वेबसाइट से ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। फतेहपुर शहर के राधानगर इलाके में करीब डेढ़ साल से यूनिक रिश्ता डॉट कॉम के जरिये लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। तीन महिलाओं समेत छह ठगों को गिरफ्तार किया गया है।

गैंग का मास्टरमाइंड आगरा का है जो आठ वैवाहिक वेबसाइट संचालित कर रहा था। गिरोह के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर महाराष्ट्र, दिल्ली, जालौन, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात में 17 शिकायतें दर्ज हैं।

साइबर क्राइम पुलिस को प्रतिबिंब पोर्टल पर महाराष्ट्र निवासी सागर राधेश्याम गुप्ता से 22,500 रुपये और कासगंज के संदेश कुमार से 2,500 रुपये की ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिली थी। जांच की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस राधानगर के देवीगंज स्थित मिलाप कोठी पहुंची। उसे राजेश पांडेय के मकान की तीसरी मंजिल पर किराये के हॉल में संगठित गिरोह संचालित होता मिला। पुलिस ने मौके से छत्तीसगढ़ निवासी आदित्य यदु, मध्यप्रदेश निवासी अनिल कुमार, छत्तीसगढ़ निवासी (हाल पता कानपुर का सीसामऊ) निवासी दिनेश कुमार बंजारा, फतेहपुर के ललौली थाने के बनरसी हरियापुर निवासी नीलम, मलवां के कांधी निवासी श्रेया मिश्रा और राधानगर बहुआ पुलिया निवासी तनु शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आगरा और कानपुर में भी पुलिस टीम को भेजा जाएगा।

ऐसे करते थे ठगी

आदित्य ने बताया कि वेबसाइट पर किसी का आवेदन आने पर कॉल की जाती थी। बताया जाता था कि आपकी प्रोफाइल को 20 लड़कियों ने पसंद किया है और वह आपसे बात करना चाहती हैं। फोटो और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के एवज में ऑनलाइन पैसे मंगवाते थे। अन्य पैकेज भी बताकर पैसे ऐंठते थे। उन्हें जिन लड़कियों की फोटो भेजी जाती थी, उनका कोई डाटा नहीं होता था। मोबाइल नंबर अपने कॉल सेंटर की लड़कियों के भेजते थे। लड़कियां बात कर जाल में फंसाती थीं और ठगी के बाद सिमकार्ड को बंद कर दिया जाता था।

मास्टरमाइंड आगरा का अमित, संचालित कर रहा था आठ वेबसाइट

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड आगरा का अमित है और आदित्य उसका सहयोगी है। ये लोग यूनिक रिश्ता डॉट कॉम वेबसाइट के जरिये शादी के इच्छुक लोगों को फंसाते थे। इनके पैकेज 2,999 से 19,999 रुपये तक के होते थे। अमित इस तरह की आठ वेबसाइट संचालित करता है। दिनेश बंजारा का कानपुर के सीसामऊ के हीरागंज में ऑफिस है। वह शुभ-मंगल नाम की वेबसाइट संचालित करता है।

हैलो आपकी प्रोफाइल 20 लोगों ने पसंद की है...बात करेंगे

हैलो सर... कैसे हैं आप। आपकी प्रोफाइल 20 लड़कियों को पसंद आई है। क्या आप बात करना चाहेंगे। इस तरह से फर्जी वैवाहिक वेबसाइट पर काम करने वाले कर्मचारी लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और साइबर ठगी करते थे। यह खुलासा राधानगर पुलिस ने किया है।

करीब डेढ़ साल से चलने वाले इस फर्जीवाड़े पर किसी की नजर नहीं गई। आसपास के लोग बताते हैं कि यहां किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। सिर्फ काम करने वाले ही कर्मचारी प्रवेश पाते थे। दरअसल अंदरखाने हर महीने आठ से 10 लाख रुपये की साइबर ठगी का खेल चल रहा था। खेल में मास्टर माइंड अमित को हर माह 50 हजार से एक लाख रुपये आदित्य भेजता था।

पुलिस की पूछताछ में आदित्य ने बताया कि वेबसाइट पर किसी का आवेदन आने पर फौरन कॉल की जाती थी। उन्हें बताया जाता था कि आपकी प्रोफाइल को 20 लड़कियों ने पसंद की है और वह आपसे बातचीत करना चाहती हैं। इसके लिए फोटो और मोबाइल नंबर के एवज में ऑनलाइन 2999 रुपये भेजने पड़ते थे।

अन्य पैकेज भी बताए जाते थे। उन्हें लड़कियों की फोटो भेज दी जाती थी जिनका कोई डाटा उनके पास नहीं होता था। मोबाइल नंबर अपने कॉल सेंटर की लड़कियों के भेजते थे। ठगी के बाद सिमकार्ड बंद कर दिया जाता था।

जिले के ललौली थाने के बनरसी हरियापुर की नीलम, राधानगर बहुआ पुलिया की तनु शर्मा, कांधी की श्रेया मिश्रा को टीम लीडर बनाया गया था। इन लोगों ने अपनी टीम में 13 लड़कियों को जोड़ा था। लड़कियों को जोड़ने के लिए पंफ्लेट बंटवाए गए थे। ऑफिस में ही विभिन्न नंबरों के मोबाइल उपलब्ध कराए जाते थे। छुट्टी के बाद मोबाइल जमा कर लिए जाते थे। लड़कियों को महीने में पांच हजार रुपये दिए जाते थे। अधिक बातचीत कर और रुपये मंगाने वाली लड़कियों को कमीशन व बोनस भी मिलता था।

कई बैंक खाते, उद्यम पोर्टल और लेबर कार्यालय में फर्म पंजीकृत

यूनिक रिश्ते के अलावा शुभ मंगल जोड़ी, शादी पार्टनर, ड्रीम पार्टनर, परफेक्ट रिश्ते, शुभ मैट्रोमोनियल, विवाह गाइड, वर-वधू डॉट कॉम नाम से ऑनलाइन फर्जी वेबसाइट संचालित करने का पुलिस ने दावा किया है। जांच में सामने आया कि उन्होंने उद्यम पोर्टल व लेबर कार्यालय में फर्म का पंजीकरण करा रखा था।

टीम लीडर तनु शर्मा के बैंक खाते में रकम का लेनदेन हुआ। आदित्य के पास अलग-अलग बैंकों के 10 डेबिट कार्ड और नौ बैंक खाते मिले। इनमें तीन बैंक खाते यूनिक रिश्ते फर्म के नाम पर थे। तीन बैंक खाते अनिल कुमार के नाम पर थे। पुलिस बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है ताकि फर्जीवाड़े का पूरा पता चल सके।

आगरा के कारगिल चौराहे का रहने वाला है अमित

पुलिस की पूछताछ में आदित्य ने बताया कि अमित कुमार आगरा जिले के कारगिल चौराहा सिकंदरा रोड बोदला पदम कुंज मकान नंबर 46 का निवासी है। करीब दो साल पहले छत्तीसगढ़ में एक बरात में अमित से मुलाकात हुई थी। नौकरी की बातचीत के दौरान उसने कहा कि हम मिलकर लड़के-लड़कियों की शादी कराने का व्यवसाय शुरू करेंगे। अनिल और दिनेश के साथ मिलकर अमित के साथ छह माह तक आगरा में एजेंट के रूप में काम किया। अच्छी कमाई होने पर दूसरे जिलों में काम शुरू किया।

ठगी की कमाई से खरीदी कार

पुलिस को बिल्डिंग के बाहर रोड पर खड़ी नई एसयूवी कार मिली जो दिनेश बंजारा की निकली। पुलिस पूछताछ में दिनेश ने बताया कि कार साइबर ठगी की कमाई से खरीदी गई। पुलिस ने कार एमवी एक्ट में सीज कर दी। आरोपियों के 10 मोबाइल नंबरों की सीडीआर जांच की गई। मैसेज में दो ऑनलाइन शिकायतें कानपुर के निवासियों की मिली।

कानपुर की नंदनी ने भेजी थी सिमकार्ड की खेप

पुलिस को एक सिम विक्रेता कंपनी के 137 नए सिमकार्ड पैक मिले हैं। यह खेप कानपुर से आई थी। सभी सिमकार्ड एक ही कंपनी के थे। साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक कमर खान ने बताया कि सिमकार्ड कानपुर की रहने वाली नंदनी ने भेजे थे। नंदनी सिमकार्ड कंपनी में काम करती है। सिमकार्ड अमित के माध्यम से पार्सल के जरिये भेजे जाते थे।

पुलिस पर उठे सवाल, मकान मालिक से होगी पूछताछ

मकान मालिक शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। उन्होंने 13 हजार मासिक किराये पर बिल्डिंग दी थी। पुलिस की जांच में मालिक के पास किराये का एग्रीमेंट मिला। हालांकि पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। एसपी ने जिले भर में कार्मिक इस्तेमाल वाले घरों की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय थाना पुलिस और एलआईयू की सर्किय्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। डेढ़ साल से चल रहे रैकेट की भनक स्थानीय पुलिस को तक नहीं लगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम 'ललितोत्सव'-2026 का आयोजन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम 'ललितोत्सव'-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डा.शक्ति सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों की वैविध्यपूर्ण प्रतिभा को रेखांकित करता है। यह कार्यक्रम संस्थान की शैक्षिक, सामाजिक गतिविधियों के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी एक बृहत प्लेटफॉर्म है। इस अवसर पर बोर्ड आफ गवर्नेंस के अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम सिंह ने कहा कि कमला नेहरू संस्थान ने शैक्षिक संस्कृति विकसित करने के साथ ही सांस्कृतिक उपलब्धि को भी प्राप्त किया है। ललितोत्सव छात्रों को सांस्कृतिक क्रियाकलाप से संपृक्त करता है। इस अवसर पर विभिन्न संकाय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में 'अपना सुल्तानपुर' की थीम पर बी.एस.सी. बायो, चतुर्थ सेमेस्टर की समीक्षा एवं खुशी को प्रथम स्थान, काजल एवं शगुन, बी.एस.सी. द्वितीय सेमेस्टर को द्वितीय स्थान तथा बी.एस.सी. बायो षष्ठम् सेमेस्टर की अंशिका अग्रहरि, नन्दिनी, अंशिका को तथा एम.एस.सी. मैथ्स द्वितीय सेमेस्टर की निधि गुप्ता और आंचल को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। रंगोली प्रतियोगिता की निर्णायक प्रोफेसर प्रतिमा सिंह रहीं। इस अवसर पर 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता - उपयोग एवं दुरूपयोग' विषय पर निबन्ध लेखन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में एम.एस.सी. जन्तु विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के निखिल ने प्रथम स्थान, बी.एड. द्वितीय सेमेस्टर की आरूषि पटेल ने द्वितीय स्थान तथा बी.काम द्वितीय सेमेस्टर की स्नेहा यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ललितोत्सव-2026 में संकाय स्तर पर प्रथम स्थान विज्ञान संकाय का, द्वितीय स्थान कला संकाय का, तृतीय स्थान वाणिज्य संकाय और चतुर्थ स्थान कृषि संकाय का रहा। कार्यक्रम के निर्णायक मण्डल में प्रोफेसर बिहारी सिंह, प्रोफेसर ललित द्विवेदी एवं प्रोफेसर प्रतिमा सिंह रहीं। आयोजन सचिव प्रोफेसर रंजना सिंह ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान और छात्रों के प्रति आभार ज्ञापित किया।

स्मार्ट मीटर पर रोक और गैस के दामों में कटौती को लेकर सौंपा ज्ञापन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिला कांग्रेस कमेटी सुलतानपुर ने जन समस्याओं को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर रोक लगाने और घरेलू गैस की बढ़ी कीमतों को कम करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों से आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। महंगाई के कारण मध्यम वर्ग व गरीब परिवारों का बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की ओर से भेजे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की रीडिंग सही नहीं आ रही है और उपभोक्ताओं से अधिक बिजली बिल वसूला जा रहा है। बिना समुचित जांच के कई उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि स्मार्ट

मीटर लगाए जाने से मीटर रीडरों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। ज्ञापन में घरेलू रसोई गैस की कमी और बढ़ी कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों की स्थापना पर तत्काल रोक लगाई जाए, स्मार्ट मीटर बनाने व लगाने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, मीटर रीडरों की सेवा सुरक्षित रखी जाए तथा घरेलू व व्यावसायिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कर बढ़ी कीमतों को कम किया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी को धरना, घेराव और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

ग्राम सभा की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, उच्च न्यायालय में शिकायत

सुल्तानपुर। तहसील कादीपुर के ग्राम नारा मधईपुर में ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। आरोप है कि यह कब्जा लेखपाल के संरक्षण में हुआ, जबकि स्थानीय प्रशासन 'जीरो टॉलरेंस' नीति का दावा कर रहा है। न्याय न मिलने पर प्रार्थी परेशान होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम नारा मधईपुर की ग्राम सभा की जमीन पर कुछ भूमाफिया तत्वों ने अवैध कब्जा कर लिया। कब्जा करने वाले लेखपाल की मिलीभगत से काम कर रहे थे। स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने बताया कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से गुहार लगाई। लेकिन हर बार उन्हें टाला गया। परेशान होकर प्राथी को अंततः उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगानी पड़ी। प्रार्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि लेखपाल के संरक्षण में भू-माफियाओं ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

उद्योगपति गौतम अदाणी ने परिवार सहित किए रामलला के दर्शन, बोले– ये भावुक करने वाला क्षण

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अदाणी बृहस्पतिवार को अयोध्या पहुंचे। जहां उन्होंने अपने परिवार सहित रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए भावुक और गौरव देने वाला क्षण है।

उन्होंने कहा, 'मुझे और मेरे परिवार को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक भावुक और गौरवपूर्ण क्षण है। यह मंदिर केवल भक्ति का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। भगवान राम के आदर्श हमें सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे और हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।' उन्होंने ये भी कहा कि अदाणी फाउंडेशन इस युग में गुरुकुल की इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।

इसके पहले, उनका विमान महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से अपने परिवार सहित अदाणी रामलला के दर्शन के लिए रवाना हो गए।

दिल्ली-एनसीआर में बंद हो सकती हैं 462 फैक्ट्रियां! सीपीसीबी ने दिया अल्टीमेटम, ये लापरवाही पड़ी भारी

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित 462 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है, जो प्रदूषण की निगरानी के लिए जरूरी उपकरण लगाने में नाकाम रही हैं. इन सभी कंपनियों पर अब तालाबंदी या भारी जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खास श्रेणी के उद्योगों के लिए ऑनलाइन कांटीन्यूअस इमीशन मॉनीटरिंग सिस्टम (OCEMS) लगाना अनिवार्य किया है. इस सिस्टम में आधुनिक कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और कचरे की रियल टाइम

(सीधी) निगरानी करते हैं. इन उपकरणों को सीधे CPCB के सर्वर और पोर्टल से जोड़ा जाता है. इससे अधिकारियों को दफ्तर में बैठे ही पता चल जाता है कि कौन सी फैक्ट्री तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण फैला रही है.

CPCB की जांच में पाया गया कि चिन्हित की गई 462 फैक्ट्रियों ने या तो यह सिस्टम लगाया ही नहीं है, या फिर इनके उपकरण तय मानकों के अनुरूप नहीं हैं. इसके चलते इन औद्योगिक इकाइयों से होने वाले उत्सर्जन की सटीक निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी. इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए CPCB ने संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इन इकाइयों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

कौन-कौन से जिले हैं रडार पर?

चिन्हित की गई फैक्ट्रियों में दिल्ली की 3 इकाइयां शामिल हैं. इसके अलावा NCR के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत हरियाणा के बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, पलवल, झज्जर, जींद और करनाल, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और हापुड़ और राजस्थान के अलवर और खैरथल-तिजारा शामिल हैं.

हवा की गुणवत्ता सुधारने की कवायद

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ-साथ साल भर वायु गुणवत्ता (AQI) एक गंभीर चुनौती बनी रहती है. CPCB का मानना है कि उद्योगों द्वारा रियल टाइम डेटा साझा न करना प्रदूषण नियंत्रण की राह में एक बड़ा रोड़ा है. इस कार्रवाई का उद्देश्य उद्योगों को जवाबदेह बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी इकाई गुप्त रूप से जहरीली गैसों का उत्सर्जन न कर सके.

आजाद पार्टी ने जनसमस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

कादीपुर, सुल्तानपुर। आजाद पार्टी ने जनसमस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल से संबोधित 15 सूत्रीय प्रमुख मांग पत्र ज्ञापन एसडीएम कादीपुर उत्तम तिवारी को सौंपा। आजाद पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बस अड्डे से होकर सरदार पटेल चौक होते हुए तहसील मुख्यालय तक प्रदर्शन किया। 15 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से किसानों के हदबरारी, थानों, तहसीलों, ब्लाकों में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा अनियमितता, पूर्ति निरीक्षक कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय व गौशालाओं में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार, कोर्ट द्वारा रिहाई आदेश में तहसील व थाने से सत्यापन में हो रही धांधली के मामलों को उठाया गया है। इसके अलावा कृषकों के दैवीय आपदा में नष्ट हो रही फसलों पर मुआवजा देने, ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति, अनियमितता के चलते जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने में आ रही।

स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, मरीजों में भी भारी असंतोष

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक साथ 6 चिकित्सकों समेत 43 कर्मचारियों को बिना स्पष्ट कारण बताओ नोटिस के रिलीव किए जाने के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर संकट गहरा गया है। इस अचानक लिए गए निर्णय से न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि आम मरीजों में भी भारी असंतोष और चिंता का माहौल बन गया है। सुल्तानपुर जनपद का जिला चिकित्सालय जो आसपास के जिलों की अपेक्षा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को प्रदान करता था वह अब जिला अस्पताल नहीं रहा जिला चिकित्सालय का अस्तित्व 1 अप्रैल से समाप्त हो गया है यहां के जनप्रतिनिधि जिला चिकित्सालय को बचाने में असफल रहे। आगे देखिए जिला अस्पताल कहीं बनता है कि जनपद वासियों का इलाज स्वशासी मेडिकल कॉलेज में ही होता रहेगा जहां पर मरीजों का इलाज सशुल्क होगा अभी भी मरीज को इलाज के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है अगर मरीज सुविधा शुल्क नहीं देता तो उसे ऑपरेशन जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। जो लोग सुविधा शुल्क देते हैं उनका काम आसानी से हो जाता है। बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्राचार्य द्वारा यह कार्रवाई की गई, लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कारण सार्वजनिक नहीं किया गया। इससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और वे अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। बिना कारण के रिलीज किए गए कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय में जाकर अपनी जोइनिंग दे रहे हैं इनमें से अधिकतर कर्मचारियों का रिटायरमेंट नजदीक है ऐसे लोगों को दूर-दराज पटक दिया गया। आठ चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग के और अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिसमें से सात चिकित्सक अपनी निजी क्लीनिक या नर्सिंग होम चलाने में व्यस्त है। इधर, मेडिकल कॉलेज में पहले से तैनात कई चिकित्सकों पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि वे सरकारी दायित्वों की अनदेखी कर अपने-अपने निजी नर्सिंग होम और क्लीनिकों में अधिक समय दे रहे हैं। एक चिकित्सक तो ऐसे हैं कि वह पिछले तीन सालों से कभी ओपीडी कक्ष में बैठे ही नहीं है वह ओपीडी आवर में अपने नर्सिंग होम में सेवाएं देते हैं और तनख्वाह सरकार से लेते हैं। इनके खिलाफ प्राचार्य भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में स्टाफ की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है।

वरिष्ठ समाजसेवी मारकंडेय यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। गोरक्षपीठ के अनन्य भक्त एवं वरिष्ठ समाजसेवी, पिपराइच क्षेत्र के लुहसी गांव निवासी मारकंडेय यादव के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह लुहसी स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।मारकंडेय यादव का बुधवार सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनकी गोरक्षपीठ के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा थी।मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह करीब सवा दस बजे लुहसी स्थित उनके आवास पहुंचे। उन्होंने पार्थिव शरीर एवं चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने परिजनों—पत्नी गुड्डी यादव, पुत्र संजीव यादव व विशाल यादव, भाई हरेंद्र यादव, पुत्री वंदना यादव तथा दामाद हिमांशु यादव से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।इस अवसर पर गोरखपुर के महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति संतराज यादव, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, पिपराइच नगर पंचायत के चेयरमैन संजय मद्धेशिया, वरिष्ठ नेता राधेश्याम सिंह, आनंद शाही, रणविजय सिंह मुन्ना सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

ऐशबाग स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक 15 जुलाई तक होगा पूर्ण, पर्यटन मंत्री ने किया निरीक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि लखनऊ के ऐशबाग स्थित संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण आगामी 15 जुलाई 2026 तक पूर्ण कर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह स्मारक एक प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे भव्य स्वरूप देने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सदस्य विधान परिषद लाल जी प्रसाद निर्मल तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी के साथ निर्माणाधीन स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को सभी कार्य गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

एसजीपीजीआई में होने जा रहा भारत का पहला कॉन्क्लेव : टेली-रोबोटिक सर्जरी के लिए नई उम्मीद बना रोबोकॉप्स 2026

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के टॉप चिकित्सा संस्थान एसजीपीजीआई में एक खास कॉन्क्लेव होने जा रहा है। जिसका आगाज कल यानी 3 अप्रैल से होगा। इस कॉन्क्लेव का नाम रोबोकॉप्स 2026 रखा गया है। जिसकी मेजबानी का जिम्मा संस्थान के पीडियाट्रिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी विभाग के ऊपर है।

यह पूरा कॉन्क्लेव पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी के भविष्य की एक झलक दिखायेगा। इतना ही नहीं आने वाले समय में टेली सर्जरी की नई उम्मीद भी पैदा करेगा। रोबोकॉप्स 2026 में देश दुनिया के कई दिग्गज पीडियाट्रिक सर्जन शामिल होंगे। जो 200 से अधिक डॉक्टर्स को पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी के गुर सिखायेंगे। यह जानकारी संस्थान के पीडियाट्रिक सर्जरी सुपर स्पेशलिटी विभाग के एचओडी प्रो.बसंत कुमार ने गुरुवार को दी है।

उन्होंने बताया कि यह अत्यंत गर्व का विषय है कि एसजीपीजीआईएमएस रोबोकॉप्स 2026 का आयोजन कर रहा है। 3 अप्रैल से शुरू होने वाले पीडियाट्रिक सर्जन का तीन दिवसीय प्रमुख रोबोटिक सर्जरी सम्मेलन 5 अप्रैल तक चलेगा। ₹ रोबोटिक नवाचार के माध्यम से पीडियाट्रिक सर्जरी के भविष्य को आगे बढ़ाना₹ विषय पर केंद्रित इस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्देश्य सबसे कम उम्र के और सबसे संवेदनशील मरीजों यानी की बच्चों के उपचार में रोबोटिक प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी भूमिका का पता लगाना है। इस कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन पहले दिन एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन द्वारा किया जाएगा, जो समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

यह सम्मेलन शुक्रवार को एसजीपीजीआई स्थित लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के डीके छाबड़ा सभागार में एक व्यापक सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। पहला दिन रोबोटिक्स के तकनीकी और आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों को समर्पित है, जिसमें रोबोटिक प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर और डॉकिंग रणनीतियों पर विशेषज्ञ सत्र शामिल हैं।

क्या है टेली रोबोटिक सर्जरी

डॉ. बसंत कुमार के मुताबिक टेली-रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है, जिसके जरिये एक सर्जन मरीज से सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए सफल ऑपरेशन कर सकता है। यह तकनीक ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञों की कमी को दूर कर सकती है, जिससे दूरदराज के मरीजों को भी बेहतरीन इलाज मिल सकता है।

मानक से नीचे मिली 11 केवी लाइन, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर अवर अभियंता निलंबित

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बलिया जाते समय गाजीपुर जनपद में निरीक्षण के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन मानक से अधिक नीचे पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश पर विभाग ने संबंधित अवर अभियंता को निलंबित करते हुए अधिशासी अभियंता के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर के अंतर्गत विद्युत वितरण खंड जंगीपुर क्षेत्र में महरौर से रसड़ा मार्ग पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान 11 केवी विद्युत लाइन मानक से अधिक नीचे पाई गई, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में विद्युत उपकेंद्र महरौर के अवर अभियंता धर्मेंद्र पाल को

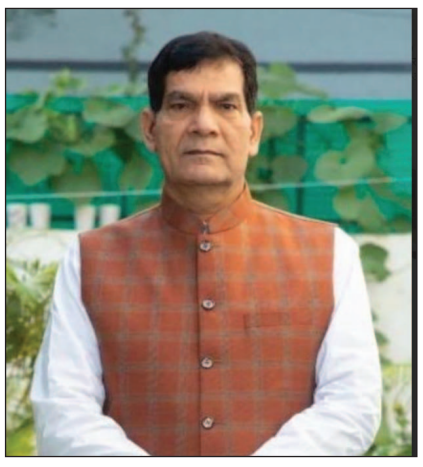

विभागीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने का प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए देर रात निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड जंगीपुर, गाजीपुर प्रवीण कुमार तिवारी को भी आरोप पत्र निर्गत किया गया है।मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट कहा कि विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विशेषकर सुरक्षा मानकों से जुड़ी अनदेखी, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सभी विद्युत लाइनों का मानकों के अनुरूप रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहे।उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

फर्जी वसीयत बनाकर जमीन हड़पने की आरोपी महिला गिरफ्तार

लखनऊ। कमिश्नरेट लखनऊ में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बिजनौर पुलिस ने कूटरचित व फर्जी तरीके से वसीयत तैयार कर भूमि हड़पने के मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है।पुलिस के अनुसार, 12 नवम्बर 2025 को विनय कुमार निवासी ग्राम बलसिंहखेड़ा, परवर पश्चिम थाना बिजनौर ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आशीष कुमारी उर्फ राजरानी, राजेन्द्र, पुनीत कुमार यादव और राजकुमारी द्वारा कूटरचित व फर्जी वसीयत तैयार कर उनकी भूमि हड़प ली गई। साथ ही वादी और उसके भाई के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस संबंध में थाना बिजनौर में मु0अ0सं0 319/2025 के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।मामले की जांच के दौरान नामजद अभियुक्ता आशीष कुमारी उर्फ राजरानी की लगातार तलाश की जा रही थी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के पिता राधेश्याम पाठक के निधन पर भाजपा नेताओं ने जताया शोक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक के पिता एवं जनसंघ काल के वरिष्ठ कार्यकर्ता राधेश्याम पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।राधेश्याम पाठक जनसंघ काल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और आजमगढ़ से जनसंघ के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे। उन्होंने संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।राधेश्याम पाठक के निधन पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह, कान्ताकर्दम, संतोष सिंह, सलिल विश्नोई, सत्यपाल सिंह सैनी, नीलम सोनकर, कमलावती सिंह, बृजबहादुर, सुनीता दयाल, दिनेश कुमार शर्मा, मानवेन्द्र सिंह, पद्म सेन चौधरी, मोहित बेनीवाल, धर्मेन्द्र सिंह, देवेश कोरी, त्रयंबक त्रिपाठी सहित अनेक पदाधिकारियों ने भी शोक व्यक्त किया।इसके अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ल, अमर पाल मौर्य, अनूप गुप्ता, प्रियंका सिंह रावत, संजय राय, सुभाष यदुवंश, राम प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश मंत्री शंकर गिरि, चन्द्रमोहन सिंह, मीना चौबे, अंजुला माहौर, विजय शिवहरे, शंकर लोधी, शकुन्तला चौहान, अनामिका चौधरी, पूनम बजाज, अर्चना मिश्रा, अमित वाल्मीकि, बंसत त्यागी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव तथा शिव कुमार पाठक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी राधेश्याम पाठक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

○ संक्षेप ○

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 3 व 4 अप्रैल को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 3 व 4 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, केशव प्रसाद मौर्य 3 अप्रैल को लखनऊ से प्रस्थान कर पूर्वाह्न 11:25 बजे सर्किट हाउस प्रयागराज पहुंचेंगे। इसके बाद वे पार्टी कार्यालय में नव नियुक्त पदाधिकारियों (महानगर, गंगापार एवं यमुनानगर) के साथ भेंटवार्ता करेंगे। अपराह्न 1:45 बजे वे 571 बाघमबरी गद्दी, अल्लापुर स्थित पार्षद विनय कुमार मिश्रा (सिन्टू) के आवास पर जाएंगे और इसके बाद पुनः सर्किट हाउस लौटेंगे।अपराह्न 4:30 बजे उप मुख्यमंत्री सिविल लाइन्स स्थित होटल कंफर्ट इन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला के अंतर्गत सिविल लाइन्स मंडल कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे तथा प्रथम सत्र में सरकार की उपलब्धियों पर उद्बोधन देंगे। इसके पश्चात अपराह्न 5:25 बजे वे ज्वालादेवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स में आयोजित विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस प्रयागराज में करेंगे।4 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री पूर्वाह्न 10:00 बजे सर्किट हाउस प्रयागराज में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा किए जाने की संभावना है।

पॉक्सो एक्ट के वारण्टी अभियुक्त को चौक पुलिस ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ अमरेन्द्र कुमार सेंगर द्वारा अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखने, पूर्व में घटित घटनाओं के अनावरण तथा वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में चौक पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमलेश दीक्षित एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) धनंजय सिंह कुशवाहा के निर्देशन तथा सहायक पुलिस आयुक्त चौक राजकुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक चौक नागेश उपाध्याय के नेतृत्व में थाना चौक पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट से संबंधित वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।पुलिस टीम ने मा0 न्यायालय ए.डी.जे. पॉक्सो एक्ट-03 लखनऊ से निर्गत एसटी संख्या 119/2020, केस संख्या 369/2019, धारा 363, 366, 376डी, 506, 504 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चौक लखनऊ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त लकी राज उर्फ काकू पुत्र सुरेश कुमार, निवासी 235/39 गली शाहछड़ा, थाना चौक, लखनऊ, उम्र करीब 30 वर्ष को दिनांक 02.04.2026 को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया।गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।इस गिरफ्तारी में प्रभारी निरीक्षक नागेश उपाध्याय, उपनिरीक्षक राजेन्द्र बाबू (चौकी प्रभारी गली शाहछड़ा) तथा कांस्टेबल अजय कुमार थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ की टीम की प्रमुख भूमिका रही।

सरोजनीनगर में मकान में लगी आग, पुलिस और फायर टीम की तत्परता से छह लोग व पालतू कुत्ता सुरक्षित बचाए गए

लखनऊ। सरोजनी नगर क्षेत्र में गुरुवार तड़के एक मकान में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। घटना में मकान में मौजूद सभी छह लोगों तथा एक पालतू कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दिनांक 02.04.2026 को प्रातः करीब 04:00 बजे PRV 6506 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कानपुर रोड स्थित भोले भवन, पार्थ रिपब्लिक के निकट एक मकान में आग लग गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सरोजनीनगर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस एवं फायर टीम द्वारा तत्परता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।मकान में शशि वर्मा उर्फ अजय रस्तोगी (48 वर्ष), अनीता वर्मा (48 वर्ष), शीतल वर्मा (24 वर्ष),

3 अप्रैल से आगरा से मथुरा तक 'रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा निकालेगी आप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में ब्रजप्रांत के अंतर्गत 3 अप्रैल 2026 से 9 अप्रैल 2026 तक आगरा से मथुरा तक 'रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो' पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इस पदयात्रा का शुभारंभ 3 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे शहीद स्मारक, संजय पैलेस, आगरा से किया जाएगा।ब्रजप्रांत अध्यक्ष डॉ. हृदेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह पदयात्रा अभियान के चौथे चरण का हिस्सा है। इससे पहले आयोजित तीनों चरणों की पदयात्राओं को प्रदेश की जनता का व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि यह पदयात्रा आगरा से हाथरस होते हुए मथुरा तक जाएगी और पहले दिन किदवई पार्क, सेंट जॉन्स चौराहे के पास आगरा में एक सार्वजनिक सभा भी आयोजित की जाएगी।डॉ. हृदेश चौधरी ने कहा कि इस पदयात्रा के माध्यम से युवाओं को रोजगार, वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय तथा प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं, किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई का सशक्त मंच बनेगा।उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है और नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि सामाजिक न्याय की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। सरकार केवल घोषणाओं और प्रचार तक सीमित है, जबकि आम जनता को न रोजगार मिल रहा है और न ही न्याय मिल पा रहा है।

छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को राहत, समाज कल्याण विभाग फिर खोलेगा पोर्टल

लखनऊ। किसी भी कारणवश छात्रवृत्ति से वंचित रह गए छात्रों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के छूटे हुए छात्रों के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने जा रहा है, ताकि सभी पात्र छात्र-छात्राएं दोबारा आवेदन कर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकें। इस सुविधा का लाभ सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलेगा। विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य छात्र केवल तकनीकी या अन्य कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के तहत पोर्टल खोला गया था, जिसके माध्यम से 53,041 छात्रों को कुल 81.12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई थी।

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर रैली आयोजित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में शहर में आयोजित एक जागरूकता रैली में दिव्यांग विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा नगर स्थित आशाज्योति विशेष स्कूल एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया गया था। इसमें शामिल लोगों ने आम लोगों को विश्व ऑटिज्म के लिए जागरूक किया।

बता दें कि विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिवस है (जो प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है) जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ऑटिज़्म के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने, ऑटिस्टिक व्यक्तियों की स्वीकृति, सराहना और समावेशन को बढ़ावा देने और ऐसे व्यक्तियों के स्थानीय और वैश्विक योगदान को मान्यता देने के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह तिथि विश्व ऑटिज़्म जागरूकता माह की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए चुनी गई थी, जो एक समान उद्देश्य को पूरा करता है। इस रैली में स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ उनके अध्यापक एवं अभिभावक भी मौजूद रहे।

झंडी वाला पार्क में 456 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल शुरू

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा शहर के समग्र विकास और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जोन-1 अंतर्गत झंडी वाला पार्क में आयोजित कार्यक्रम में लगभग ₹2962.60 लाख की लागत से निर्मित सड़कों, नालियों और पार्कों सहित कुल 456 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर कल्याण मंडपों एवं सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सुषमा खर्कवाल उपस्थित रहीं। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें शहरवासियों को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से शहर में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया गया है, जिसमें सड़कों का

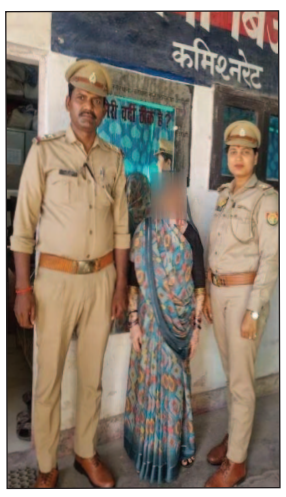

निर्माण एवं चौड़ीकरण, नालियों का सुदृढ़ीकरण तथा पार्कों का सौंदर्यीकरण शामिल है। इन कार्यों से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और स्वच्छता व हरित वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा।कार्यक्रम में कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरनजीत गांधी, उपनेता पार्षद दल भाजपा सुशील तिवारी 'पम्मी', नगर आयुक्त गौरव कुमार, जोन-1 के पार्षद सफीकुर रहमान 'चचा', गिरीश गुप्ता, आशीष हितैषी, यावर हुसैन रेशु, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अरुण कुमार गुप्त, मुख्य अभियंता महेश वर्मा, नगर अभियंता अतुल मिश्रा सहित कई पार्षद, अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।महापौर सुषमा खर्कवाल ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग ₹2962.60 लाख की लागत से तैयार 456 परियोजनाएं लखनऊ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी होने के साथ तेजी से विकसित होता आधुनिक शहर भी है, ऐसे में विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि विकास कार्यों के साथ उनकी देखभाल भी जरूरी है और सभी लोग स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।कार्यक्रम के दौरान नगर निगम द्वारा कल्याण मंडपों और सामुदायिक केंद्रों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा का शुभारंभ भी किया गया। इस नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब घर बैठे ही विभिन्न मंडपों और सामुदायिक केंद्रों की उपलब्धता देख सकेंगे तथा ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। इस पहल से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।नगर निगम द्वारा महानगर, जियामऊ, मानसरोवर, विकास नगर, आनंद नगर, सरस्वती नगर, लालबंगला, नरही, गणेशगंज और सरोजनी नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के कल्याण मंडपों एवं सामुदायिक केंद्रों के लिए निर्धारित शुल्क भी जारी किए गए हैं, जिनकी बुकिंग अब ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी।

अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से युवक की मौत, परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज

लखनऊ। अनूपगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से टकराकर एक युवक की हुई मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद व अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.2026 को समय करीब 22:30 बजे थाना कार्यालय पर सूचना प्राप्त हुई थी कि अनूपगंज रेलवे स्टेशन के पास एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से टकरा गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि अनूपगंज स्टेशन की मध्य लाइन पर एक युवक ट्रेन से टकरा गया था। उस समय मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी तथा उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष प्रतीत हो रही थी। शव का पंचायतनामा आदि की कार्रवाई जीआरपी द्वारा की गई।

बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर 4 अप्रैल को कांग्रेस की विशाल गोष्ठी व सम्मान समारोह

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व उप प्रधानमंत्री, समाज सुधारक एवं वरिष्ठ राजनेता बाबू जगजीवन राम की जयंती की पूर्व संध्या पर 04 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय (पूर्व मंत्री) ने जानकारी दी कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. रतन लाल

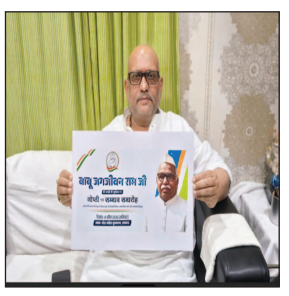

विशेष रूप से शामिल होंगे।उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुसूचित जाति के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों एवं विधायकों के साथ-साथ समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा।अजय राय ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपने जीवन में सामाजिक समता, न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। "समता दिवस" के आयोजन का उद्देश्य उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना तथा समाज में समानता और सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता को सुदृढ़ करना है।उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने देश के कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा रक्षा मंत्री के रूप में वर्ष 1971 के युद्ध में अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को जननायक राहुल गांधी समर्पण के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

तेल कम, गैस कम...आने वाले दिनों में क्या बिजली भी होगी कम? बढ़ती गर्मी के बीच लोगों के मन में नई टेंशन!

भीषण गर्मी ने अभी से ही लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में तापमान किस स्तर तक पहुंच सकता है। देश के कई हिस्सों में मार्च के अंतिम सप्ताह से ही तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोग अब खाना पकाने जैसे घरेलू कार्यों के लिए भी बिजली पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऐसे में जब अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी अपने चरम पर होगी, तब बिजली की मांग में भारी उछाल आना लगभग तय माना जा रहा है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि इस वर्ष भारत में अधिकतम बिजली मांग दो लाख पचास हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा। पिछले वर्ष भी गर्मी के मौसम में मांग ने कई रिकॉर्ड तोड़े थे और करीब दो लाख तीस हजार मेगावाट तक पहुंच गई थी। इस बार तापमान अधिक रहने की संभावना के चलते मांग और अधिक बढ़ सकती है। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व क्षेत्र दुनिया के प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता माने जाते हैं। यहां जारी तनाव का सीधा असर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। हालांकि भारत अपनी बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा कोयले से पूरा करता है, लेकिन गैस आधारित बिजली संयंत्र और आयातित ईंधन भी ऊर्जा संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होती है तो इसका असर भारत की ऊर्जा लागत पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है। शहरों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव के कारण लोग अब गैस की जगह बिजली आधारित उपकरणों का अधिक उपयोग करने लगे हैं। इंडक्शन चूल्हे, बिजली से चलने वाले हीटर और अन्य उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल ने कुल बिजली खपत को और बढ़ा दिया है।

हम आपको बता दें कि भारत की बिजली व्यवस्था अभी भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर है। कुल बिजली उत्पादन का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा कोयला आधारित बिजली घरों से आता है। गर्मी के मौसम में जब मांग बढ़ती है, तब कोयले की खपत भी तेजी से बढ़ती है। कई बार यह स्थिति पैदा हो जाती है कि बिजली घरों के पास सीमित दिनों का ही कोयला भंडार बचता है। कोयला खदानों से उत्पादन, रेलवे के जरिए परिवहन और बिजली घरों तक आपूर्ति की पूरी श्रृंखला पर दबाव बढ़ जाता है। यदि इस श्रृंखला में कहीं भी बाधा आती है तो इसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ सकता है। यही कारण है कि हर साल गर्मी के मौसम में कोयले की उपलब्धता एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। देखा जाये तो बढ़ती मांग और ईंधन की लागत में संभावित वृद्धि के चलते बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि बिजली उत्पादन की लागत बढ़ती है, तो वितरण कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि सरकार आम जनता पर बोझ कम रखने के लिए सब्सिडी और अन्य उपायों का सहारा ले सकती है, लेकिन लंबे समय तक यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं मानी जाती। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक ऊर्जा कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और घरेलू मांग लगातार बढ़ती है, तो भविष्य में बिजली दरों में संशोधन करना पड़ सकता है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले महीनों में बिजली कटौती बढ़ेगी? यदि मांग और आपूर्ति के बीच अंतर अधिक बढ़ता है, तो कई राज्यों में बिजली कटौती की स्थिति बन सकती है। खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में भी पीक समय के दौरान दबाव बढ़ सकता है। जब घरों, दफ्तरों और बाजारों में एक साथ बिजली की खपत बढ़ती है, तब ग्रिड पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। यदि पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध नहीं होता, तो लोड प्रबंधन के तहत कटौती करनी पड़ सकती है। उधर, केंद्र सरकार ने इस चुनौती को देखते हुए पहले से ही कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने, बिजली घरों में न्यूनतम भंडार सुनिश्चित करने और राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि मांग प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है।

नक्सलवाद मुक्त भारत की डेडलाइन पूरी, ख्वाब अधूरी, अब अर्बन नक्सलियों पर नजर!

आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियाँ बनी हुई हैं। फरवरी 2026 तक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6-7 रह गई थी

कमलेश पांडे

देश के 'पीएम इन वेटिंग' और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों और आतंकवादियों की कमर तोड़ने में अभूतपूर्व और उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि भारत अभी पूरी तरह नक्सलवाद और आतंकवाद मुक्त हुआ है। हां, सरकार की कोशिशें सराहनीय हैं। यदि शाह अपने नेक मकसद में कामयाब हुए तो प्रधानमंत्री पद की उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मनमाफिक राष्ट्रीय टीम पहले से ही बना रखी है।

यह ठीक है कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, और आतंकवाद समाप्ति को लेकर ऐसा कोई दुरूह लक्ष्य घोषित नहीं किया गया था और कड़ी कार्रवाई गतिमान है, लेकिन पूरे देश की बात छोड़ दी जाए तो खुद दिल्ली-एनसीआर से ब्रेक के बाद सामने आने वाले मामले इस बात की चुगली कर रहे हैं कि उद्देश्यपूर्ति काफी जटिल है।

ऐसा इसलिए कि नक्सलियों और आतंकवादियों को बौद्धिक और आर्थिक खुराक देने वाली जमात राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक हलकों में सक्रिय हैं! प्रशासनिक गलियारों तक में इनकी जातिवादी और सांप्रदायिक पैठ है।जबतक इनकी शिनाख्त और गिरफ्तारी नहीं होती, उद्देश्य अधूरा रहेगा। संभव हो कुछ तत्व सत्ताधारी दल से भी डायरेक्ट या भाया मीडिया सम्बन्धित हों।

आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियाँ बनी हुई हैं। फरवरी 2026 तक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6-7 रह गई थी, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र (बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर) में। वहीं, मार्च 2026 के अंत में सुकमा में नक्सली मुठभेड़ हुई, जहाँ एक नक्सली मारा गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि नक्सलवाद लगभग समाप्ति की कगार पर है, लेकिन औपचारिक घोषणा प्रक्रिया पूरी होने पर होगी। सरकारी दावा करते हुए अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को लोकसभा में कहा कि ₹देश नक्सल मुक्त हो चुका है₹ और ₹नक्सलवाद विलुप्ति की ओर है।₹ 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के ठीक पहले भी ऑपरेशन चल रहे थे, जिसमें सैकड़ों नक्सली मारे गए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। फिर भी, बस्तर जैसे क्षेत्रों में सीमित गतिविधियाँ जारी हैं।

प्रगति के आंकड़े बताते हैं कि नक्सल प्रभावित जिले 126 (2010) से घटकर 6-7 (2026) पर पहुंच गए और ज्यादातर नक्सली मारे गए। 700+ तो हाल के वर्षों में।वहीं, आत्मसमर्पण करने वाले 4,800+ नक्सली दूसरे धंधों में जुड़ चुके हैं। बहरहाल, नक्सलवाद बहुत कमजोर हो चुका है, लेकिन पूर्ण मुक्ति की घोषणा अभी बाकी है। भारत में नक्सल प्रभावित 6 जिलों की स्थिति काफी संवेदनशील बनी हुई है, जहाँ सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। ये जिले मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में केंद्रित हैं।

वहीं, सबसे अधिक प्रभावित जिले निम्नलिखित 6 जिले हैं, जिनके नाम छत्तीसगढ़ (बीजापुर, कांकेर/नारायणपुर, नारायणपुर, सुकमा), झारखंड (पश्चिमी सिंहभूम), और महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) हैं। इनमें नक्सली गतिविधियाँ सीमित लेकिन सक्रिय हैं, जैसे छिपे हुए कैंप और छोटे हमले। सुरक्षा बलों ने हाल के ऑपरेशनों से इन क्षेत्रों में घुसपैठ बढ़ाई है।

जहां तक वर्तमान अभियान की बात है तो छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद (कभी-कभी सूचीबद्ध) में हाई-अलर्ट सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सरकार ने अंतिम बड़े अभियान की तैयारी की है, जिसमें आत्मसमर्पण और मुठभेड़ों पर जोर है। मार्च 2026 तक हिंसा में भारी कमी आई, लेकिन पूर्ण नियंत्रण बाकी है।वहीं प्रगति संकेत यह है कि नक्सली संख्या घटी, सैकड़ों आत्मसमर्पण हुए। विकास परियोजनाएँ शुरू हुईं, जैसे सड़कें और स्कूल।

फिर भी, जंगलों में छिटपुट गतिविधियाँ जारी हैं। लिहाजा, 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद भी इन जिलों पर फोकस रहेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने नक्सल प्रभावित 6 जिलों (मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बीजापुर, कांकेर/नारायणपुर, सुकमा, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरोली) को नक्सल मुक्त करने के लिए बहुआया रणनीति अपनाई है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक पूर्ण मुक्ति का लक्ष्य रखती है, जिसमें सुरक्षा अभियान, आत्मसमर्पण नीति और विकास पर जोर है। सुरक्षा अभियान भी जारी है।

सुरक्षा बलों ने इन जिलों में सघन सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं, जैसे कुर्रेगुट्टालू पहाड़ मॉडल पर आधारित लंबे अभियान। नक्सलियों के सहयोगी नेटवर्क (एड नेटवर्क) को निशाना बनाया जा रहा है, साथ ही 576 मजबूत पुलिस स्टेशन और 336 नए कैंप स्थापित किए गए। मुठभेड़ों और घेराबंदी से नक्सली कमांडरों को खत्म करने पर फोकस है।

वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास पर बल दिया गया है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए उदार नीति लागू है, जिसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार दिया जाता है। हाल के वर्षों में हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। पकड़े गए या आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। विकास पहल तेज है। इन जिलों में 137 केंद्र योजनाओं का तेज वितरण, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो रहे। एसआरई योजना के तहत क्षमता निर्माण जारी रहेगा ताकि नक्सलवाद न लौटे। 10-सूत्री योजना में वित्तीय सहायता प्रणाली तोड़ना और स्थानीय विकास शामिल है।

फिर भी अपेक्षित परिणाम की उम्मीद पूरी होनी अभी बाकी है। सरकार ने ठीक ही कहा है कि 31 मार्च 2026 के बाद 'अर्बन नक्सल' पर नजर रखी जाएगी। ये प्रयास नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के करीब हैं, लेकिन जंगलों में छिटपुट चुनौतियाँ बाकी हैं। रही गई बात आतंकवाद की तो इसे पर्दे के पीछे से धर्म और डिप्लोमैट बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इनसे निबटने में अभी वक्त लगेगा।

टिप्पणी

युद्ध से नियंत्रण खो चुके ट्रंप

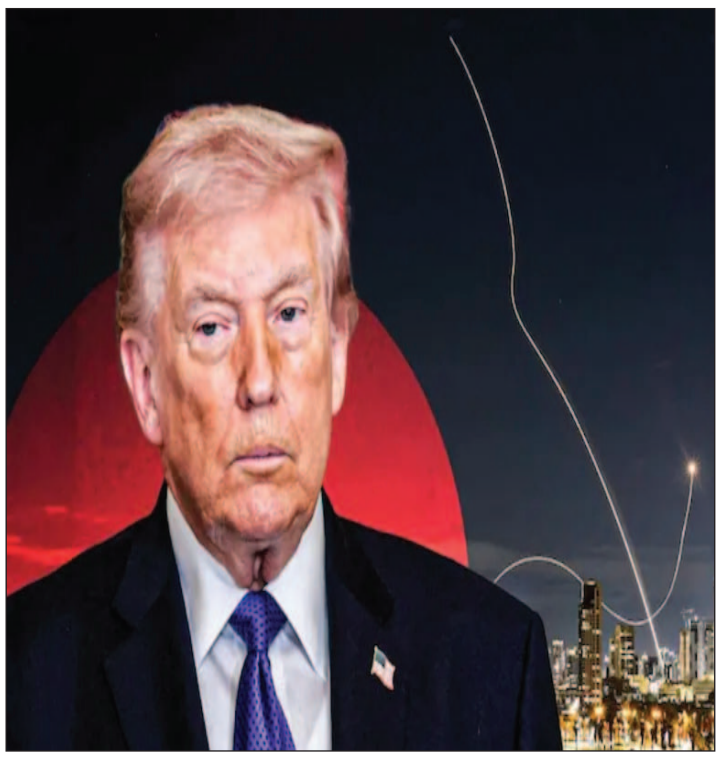

ट्रंप की टिप्पणियां संकेत हैं कि ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध से निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। ट्रंप युद्ध पर से अपना नियंत्रण खो चुके हैं, जिसकी बेचैनी उनके बयानों से जाहिर हुई है।

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के उलझते जाने की स्थिति से व्यग्र डॉनल्ड ट्रंप अपनी नाकामी का ठीकरा नाटो में अपने सहयोगी देशों और चीन फोड़ते नजर आ रहे हैं। उलझाव का आलम यह है कि ईरान में थल सेना उतारने पर उनका प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहा है, जिसकी शुरुआत ईरानी द्वीप खर्ग से हो सकती है। अफगानिस्तान और इराक के अनुभवों के मद्देनजर अमेरिका के युद्ध रणनीतिकार इसे अपने देश के लिए खतरनाक फैसला मानते हैं। बहरहाल, वहां थल सेना भेजने के बावजूद होरमुज जलडमरूमध्य को खुलवाने का सवाल बना रहेगा। नौसैनिक हस्तक्षेप के जरिए ऐसा करने में अमेरिका अकेले खुद को अक्षम पा रहा है।

इसलिए ट्रंप ने चीन सहित कई देशों से मदद करने की गुजारिश की। चीन ने तो इसे सीधे ठुकरा दिया, जबकि अमेरिका के सहयोगी माने जाने वाले किसी देश से भी तुरंत सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। तो अब ट्रंप ने यूरोपीय देशों की अनिच्छा के मद्देनजर नाटो के ₹बहुत बुरे भविष्य₹ की धमकी दी है। उधर चीन को चेताया है कि वे 31 मार्च से तय अपनी बीजिंग यात्रा स्थगित कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेज़ेस्कियान से बात कर फ्रेंच जहाजों के लिए होरमुज का रास्ता खोलने का आग्रह किया।

उन्होंने जोर किया कि फ्रांस इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। यह संकेत है कि यूरोपीय देश अमेरिका- इजराइल के बिना तय सैन्य उद्देश्य वाले युद्ध में भागीदारी से बच रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानी हमलों में हो रहे नुकसान के कारण अमेरिका के अंदर युद्ध लगातार अधिक अलोकप्रिय होता जा रहा है। चूंकि नुकसान की खबरें अमेरिका के बड़े अखबारों ने छापी हैं, तो उससे भड़के ट्रंप ने उन अखबारों पर राष्ट्र-द्रोह का इल्जाम मढ़ दिया है। मगर उनकी ऐसी प्रतिक्रियाओं को इसी बात संकेत समझा गया है कि ट्रंप प्रशासन ने बिना रणनीति बनाए देश को ऐसे युद्ध में झोंक दिया, जिससे निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। यानी ट्रंप युद्ध पर से अपना नियंत्रण खो चुके हैं। इसकी बेचैनी उनके बयानों से जाहिर हो रही है।

ब्लॉग

संवैधानिक संस्थाओं पर उठते सवालों से कमजोर होता लोकतंत्र

योगेंद्र योगी

देश में समय के साथ लोकतंत्र के परिपक्कव होने के बजाए कमजोर होने की आहट आ रही है। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर—तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के इस घेरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक और अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने ₹पक्षपातपूर्ण व्यवहार₹ दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है। ₹₹पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था। कई बार मुझे बोलने से रोका गया है। पहली बार लोकसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है।

नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51% थी। नेशनल एवरेज 66% था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% थी। नेशनल एवरेज 80% था। 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43% थी, जबकि नेशनल एवरेज 76% था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर बिरला के कामकाज के तौर—तरीकों पर उनको हटाने का प्रस्ताव लाकर नाराजगी जताने से पहले राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़ पर इसी तरह के आरोप लगाते हुए विपक्ष ने दिसंबर 2024 में उन्हें पद से हटाने का नोटिस दिया था। विपक्ष का आरोप था कि राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ने आरोप लगाया था कि कि धनखड़ एक सरकारी प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो अक्सर अनुभवी विपक्षी नेताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें सदन में बोलने से रोकते हैं। खरगे ने यह भी दावा किया था कि सदन में हुई गड़बड़ी के लिए स्वयं श्री धनखड़ जिम्मेदार हैं।

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष का सभापति धनखड़ को हटाने का नोटिस खारिज कर दिया था, जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की गई थी। हरिवंश ने यह कहते हुए विपक्ष का नोटिस खारिज कर दिया कि यह तथ्यों से परे है और इसका मकसद केवल प्रचार हासिल करना है। उपसभापति ने कहा था कि धनखड़ के खिलाफ नोटिस अनुचित और त्रुटिपूर्ण है, जिसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया है। राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है।

इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया गठबंधन) के घटक दलों ने सभापति धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 दिसंबर को राज्यसभा के महासचिव को सौंपा था। नोटिस पर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के 60 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके नेता तिरुचि शिवा और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर रॉय, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, मुख्य सचेतक जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला तथा कई अन्य सीनियर सदस्यों ने धनखड़ के खिलाफ दिए गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।

संसद के दोनों सदनों के प्रमुखों के खिलाफ हटाने के प्रयासों के अलावा विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में सौंपा है। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को हटाने के विपक्ष के प्रयास सफल नहीं हो सके, उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग के भी पारित होने की संभावना क्षीण है। विपक्ष के पास महाभियोग पारित कराने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। इस तरह के संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों को हटाने के लिए एकजुट विपक्ष के प्रयास बेशक सफल नहीं हो पाएं, किन्तु ऐसे प्रयासों से इन पदों की गरिमा कम हुई है। देश में विपक्ष को पूरी तरह से खारिज करके मजबूत लोकतंत्र की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता।

संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर उठते सवालों के घेरे में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कैग) का पद भी आ चुका है। इस पद के चयन के लिए कमेटी बनाने की मांग पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका लंबित है। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की याचिका में कहा गया है कि अभी कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। इस पद की अहमियत को देखते हुए इसके लिए योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति का चयन जरूरी है इसलिए, सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के जरिए कैग के चयन का आदेश दे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर उठते सवाल भारतीय लोकतंत्र में एक गंभीर विषय बन गए हैं। इन संस्थाओं को परिपक्वता से काम करना चाहिए ताकि उन पर सवाल न उठें। विपक्ष का आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि वे संविधान के अनुसार काम कर रही हैं। यह बहस लोकतंत्र के लिए जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

खून से चुकाया एहसान! मुरादाबाद में जज के पिता की हत्या में आसिफ का क्या था रोल? 'मामा' ने भांजे को बनाया मोहरा

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते 27 फरवरी को जज के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नागफनी थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में पुलिस ने एक और आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी जफर हुसैन और उसके दोनों बेटे फरार हैं। अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की पूरी साजिश आसिफ के घर पर बैठकर रची गई थी। आरोपी जफर हुसैन का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह पहले दिल्ली में चोरी और जानलेवा हमले के मामलों में जेल जा चुका है। जफर का आसिफ के परिवार से करीबी रिश्ता था। वह आसिफ की मां को अपनी बहन मानता था और आसिफ उसे मामा कहकर बुलाता था। दरअसल, जफर का एक करीबी दोस्त जरीफ था, जिसके साथ वह लंबे समय तक आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। जरीफ की मौत के बाद जफर ने उसके परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने जरीफ के बेटे आसिफ को अपने पास रखा और धीरे-धीरे उसे भी अपराध की दुनिया में शामिल कर लिया। यही वजह रही कि जफर के कहने पर आसिफ इस साजिश में शामिल हो गया।

27 फरवरी को हुई थी हत्या

घटना 27 फरवरी की है। रोजा इफ्तार के बाद मोहम्मद असद अपने छोटे साले मुजाहिद के साथ स्कूटी से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे नागफनी इलाके के बांग्ला गांव चौराहे पर पहुंचे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने असद के सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजन मुजाहिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जफर हुसैन, उसके बेटों सैफुल हुसैन और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पहले जफर के दामाद और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार किया था, और अब आसिफ को भी पकड़ लिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जफर अपने निजी विवादों के चलते इस हत्या को अंजाम देना चाहता था। जब उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, तो उसने आसिफ को अपने साथ मिलाया। पारिवारिक रिश्तों और पुराने एहसानों के चलते आसिफ ने जफर का साथ दिया और साजिश में शामिल हो गया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी जफर और उसके बेटों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

मोहम्मद असद के बेटी जज हैं

मृतक मलिक मोहम्मद असद (62) मुरादाबाद के लाल मस्जिद इलाके के निवासी थे और व्यवसाय से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक, उनकी हत्या का मुख्य आरोपी उनका साला जफर है। बताया जा रहा है कि असद का परिवार समाज में काफी प्रतिष्ठित और सम्मानित माना जाता है। उनकी बेटी आसमान सुल्तान बुलंदशहर में एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनके दामाद भी न्यायिक सेवा से जुड़े हैं।

श्रद्धा के साथ मनाई गयी हनुमत जयन्ती

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। भगवान शिव के ग्यारवें रुद्र अवतार एवं भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त हनुमान जी की जयंती श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, बजरंग बाण व हनुमाष्टक का पाठ किया गया। 'जय हनुमान ज्ञान गुन सागर' के जयकारे से समूचा माहौल गूंज रहा था। मंदिरों पर हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया एवं भंडारों का आयोजन हुआ। बड़े हनुमान जी सिपाह, कोतवाली चैराहा स्थित हनुमान मन्दिर, बीआरपी इण्टर कालेज के पास हनुमान मन्दिर, मारूति मन्दिर टीडी कालेज आदि स्थानों पर सुबह से रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा श्री हनुमान का पूजन अर्चन किया गया और श्री हनुमान को 56 भोग लगाए गए। इसके अलावा शहर भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन का आयोजन हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ी रही। शहर भर में जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने को दिन भर पंक्तियां लगी श्री हनुमान को पूड़ी, सब्जी व हलुआ का भोग लगाने के बाद भंडारे की शुरूआत की गई।

चाकू घोंपने से युवक मरणासन्न, पांच गिरफ्तार

जौनपुर। खेता सराय थाना क्षेत्र के अमरेथूवा गांव में ष्शराब पीने से मना करने पर दबंगों ने चाकू मारकर युवक को मरणासन्न कर दिया। बताया गया है कि उक्त गांव निवासी 30 वर्षीय संदीप कुमार राजभर पुत्र स्व0 राम अधार गांव में ही अपने साथियों के साथ बैठा था कि उसी समय बात बात पर कहासुनी हो गई। इतने में उसके साथ रहे युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर उसके पेट के दाहीने तरफ मार दिया दिया। इतने में वहां अफरातफरी और भगदड़ मच गय ैके पर पहुंचे कुछ लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उसकी बिगड़ती हालत को देखकर बेहतर उपचार के लिए वाराणसी बीएचयू रेफर कर दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 24 घंटे के भीतर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अप्रैल को सोंगर पुलिया के पास से पांचों नामजद आरोपियोंकृसचिन राजभर, विकास राजभर उर्फ भोलू, विकास राजभर उर्फ विकेश, आदित्य राजभर व अमर राजभर उर्फ गोरेलालकृको गिरफ्तार कर लिया।

सौरभ हत्याकांड : मुस्कान–साहिल के बारे में 20वें गवाह ने कोर्ट को क्या बताया? मेरठ से भागकर हिमाचल में किया था बड़ा फर्जीवाड़ा

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड की सुनवाई कोर्ट में लगभग अंतिम में है। बुधवार को जिला जज कोर्ट में 20वें गवाह के बयान दर्ज किए गए। जिसमें कसौल स्थित पूर्णिमा गेस्ट हाउस के मैनेजर ने अहम खुलासा किया। गवाह ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मुस्कान और साहिल होटल में पति-पत्नी बताकर रुके थे। इस गवाही के बाद अब 7 अप्रैल को 21वें गवाह की पेशी होगी, जिसे मामले का महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।

पीड़ित पक्ष के वकील विजय बहादुर सिंह के अनुसार, पूर्णिमा गेस्ट हाउस के मैनेजर अमन कुमार ने कोर्ट में होटल का रजिस्टर, एंट्री रिकॉर्ड और दोनों आरोपियों के पहचान पत्र पेश किए। रजिस्टर में मार्च 2025 की वह एंट्री दर्ज है, जिसमें मुस्कान और साहिल ने खुद को पति-पत्नी बताते हुए कमरा बुक कराया था। यह गवाही पीड़ित पक्ष के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे हत्या के बाद दोनों के साथ घूमने और फरार होने की पुष्टि हो सकती है।

7 अप्रैल को होगी 21वीं गवाही

अब अदालत में 7 अप्रैल को मृतक सौरभ के दोस्त संजीव पाल की 21वीं गवाह होगी। संजीव वही व्यक्ति है, जिनसे 8 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल फोन से बात की थी। वकील के मुताबिक, जब संजीव ने अपने दोस्त सौरभ से बात करने के लिए फोन किया, तो मुस्कान ने फोन उठाकर उन्हें धमकाते हुए कहा था कि दोनों साथ घूमने आए हैं और बार-बार कॉल कर परेशान न करो। यह गवाही भी केस में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। अब तक इस मामले में 20 गवाहों की बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सौरभ के परिवार के सदस्य, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक टीम, ड्रम विक्रेता, होटल मैनेजर, कैब चालक और अन्य महत्वपूर्ण गवाह शामिल हैं। पुलिस चार्जशीट में कुल 35 गवाहों को शामिल किया गया है।

कब तक आ सकता है फैसला?

माना जा रहा है कि 21वें गवाह के बयान के बाद अंतिम बहस कोर्ट में होगी। कानूनी जानकारों के मुताबिक कोर्ट इस मामले में 15 अप्रैल तक फैसला सुना सकती है। मार्च में इस चर्चित हत्याकांड के एक साल पूरे हो गए।

ससुराल में युवक की मौत, हत्या का आरोप

जौनपुर। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के दूहावर गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। भदोही जनपद के फूलपुर निवासी करीब 30 वर्षीय जितेंद्र कुमार चैहान अपनी ससुराल दूहावर गांव आए हुए थे, जहां उनकी साली की शादी की तैयारियां चल रही थीं। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष की मांग पर उन्होंने एक लाख रुपये की व्यवस्था कर दी थी।बुधवार देर रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कहकर ससुराल पक्ष के लोग उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों को शव पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला संदिग्ध मानते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।घटना की सूचना पर पहुंचे मृतक के पिता और भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

थ्रेसर में फंसने मूक बधिक महिला की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। केराकत क्षेत्र के तेजपुर गांव में बुधवार की रात एक दर्दनाक हादसे में विवाहिता की मौत हो गई। बताया गया कि अपने खेत में गेहूं की मड़ाई के दौरान 48 वर्षीय मूकबधिर बिन्दू देवी पत्नी सुरेन्द्र राम थ्रेसर में फंस गईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही बिन्दू देवी ने दम तोड़ दिया।बताया जा रहा है कि मड़ाई के दौरान थ्रेसर ट्रैक्टर से चल रहा था, जिसे राजकुमार यादव चला रहा था। चर्चा का विषय है कि घटना के समय ट्रैक्टर चालक मौके पर मौजूद था। यदि चालक वहां सतर्क रहता, तो संभवतः हादसा टल सकता था। मृतका अपने पीछे दो पुत्र और एक नाबालिग पुत्री स्नेहा को छोड़ गई हैं। वहीं पति सुरेन्द्र राम पैर से दिव्यांग हैं, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है।

इंसानों के लिए खरीद ली जानवरों वाली सिरिंज, नोएडा के जिला अस्पताल में गजब की लापरवाही

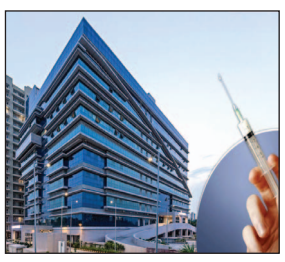

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के जिला अस्पताल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां इंसानों के इलाज के लिए ऐसी सिरिंज मंगवा ली गईं, जो असल में जानवरों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। अस्पताल में रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सिरिंज की जरूरत को देखते हुए सरकारी प्रक्रिया के तहत खरीद की गई थी, लेकिन जब सप्लाई अस्पताल पहुंची और स्टाफ ने उसकी जांच की, तो पता चला कि ये सिरिंज वेटरनरी यूज यानी पशुओं के लिए हैं।

इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया है कि आखिर इतनी गंभीर चूक कैसे हो गई। सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों की खरीद एक तय प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें कई स्तर पर जांच और सत्यापन शामिल होता है।

यह खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिए की गई थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि या तो ऑर्डर देते समय गलत प्रोडक्ट का चयन हुआ या फिर सप्लाई एजेंसी ने गलत सामान भेज दिया। इसके अलावा स्टाफ वेरिफिकेशन के दौरान भी लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सभी स्तरों पर सही तरीके से जांच होती, तो यह गलती पहले ही पकड़ में आ सकती थी।

वहीं, अस्पताल के कर्मचारियों की सतर्कता से इस मामले का खुलासा हो पाया। पैकेट पर For Animal Use Only लिखा देख स्टाफ को शक हुआ, जिसके बाद जांच में पूरा मामला सामने आया। अगर यह गलती पकड़ में नहीं आती, तो मरीजों के इलाज में इन सिरिंज का इस्तेमाल हो सकता था, जिससे संक्रमण या अन्य स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता था।

क्या बोले चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट?

अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट (CMS) अजय राणा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन ने निर्धारित मानकों के अनुसार ही ऑर्डर दिया था। उनके अनुसार, सप्लाई एजेंसी की ओर से गलत सामान भेजा गया है। जैसे ही मामला सामने आया, तुरंत उस स्टॉक को अलग कर दिया गया और उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए खरीद प्रक्रिया को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

जिला अस्पताल जैसे संस्थान में इस तरह की घटना सामने आना चिंता का विषय है। यह केवल एक गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करती है। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जांच जारी है। आगे की निगरानी के लिए स्टाफ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अभी तक इन सिरिंज के पैकेट को इस्तेमाल के लिए नहीं खोला गया था, सिर्फ स्टाफ की टीम ने जांच के लिए एक बॉक्स को डॉक्टरों की निगरानी में खोला था।

'पांच लाख दो नहीं तो पूरा परिवार खत्म कर देंगे', ज्वैलर्स को कारतूस और धमकी भरा पत्र भेजकर मांगी रंगदारी

आर्यावर्त संवाददाता

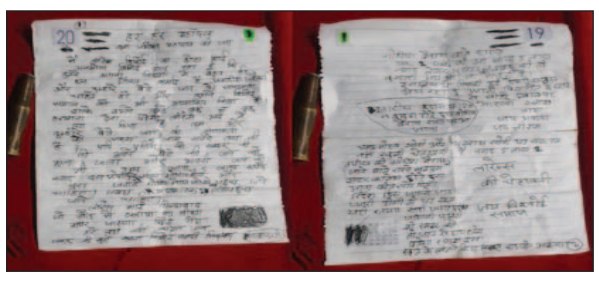

बहराइच। बहराइच में कस्बे के मुख्य बाजार में एक सराफा व्यापारी की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने बुधवार रात में धमकी भरा पत्र और जिंदा कारतूस फेंककर खुलेआम 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पत्र में साफ लिखा है कि अगर तय रकम नहीं दी गई तो व्यापारी के पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। पत्र भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आते ही इलाके में दहशत का माहौल है। जगदीश ज्वेलर्स के मालिक चंद्र मोहन सोनी उर्फ छठ ने बताया कि देर रात को पत्र मिलने के बाद अज्ञात नंबरों से कई बार फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। लगातार मिल रही धमकियों से उनके परिवार में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अब दुकान खोलना और कारोबार करना भी जोखिम भरा लगने लगा है।

घटना के बाद व्यापार मंडल ने कड़ा रुख अपनाया है। अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करता है, तो 3 अप्रैल को पूरा बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने सभी व्यापारियों, विशेषकर सर्राफा कारोबारियों से सुरक्षा के मद्देनजर अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और सतर्क रहने की अपील की है। व्यापारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे बाजार की सुरक्षा का मामला है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अपराधियों के हौसले और बढ़ सकते हैं। वहीं, इस घटना के बाद पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि अभी तक किसी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दोषियों को सख्त सजा दिलाएगी, ताकि व्यापारियों का भरोसा बहाल हो सके।

धमकी भरे पत्र में है यह हवाला

धमकी भरे पत्र में फिरौती मांगने वाले ने अपने को लारेंस विश्नोई का छोटा भाई अनमोल विश्नोई बताया है। पत्र में लिखा है कि तुमने बहुत धन कमाया है। पत्र में कहा गया है कि आज शाम 7:20 बजे गोपिया मार्ग पर दरोगा पुरवा के पास पैसा लेकर पहुंचना है। यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर पुलिस को खबर की या कोई चालाकी की तो तुम्हारे बेटे और पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पत्र के साथ 12 बोर का कारतूस भी लिपटा हुआ था।

लखनऊ–कानपुर रेल मार्ग पर 1.5 महीने तक मेगा ब्लॉक... 16 ट्रेनें रद्द, 27 के रूट बदले, इन स्टेशनों पर ही खत्म हो जाएगी यात्रा

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर सेंट्रल और कानपुर पुल (बायां किनारा) के बीच रेलवे ब्रिज पर आज गुरुवार से महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कार्य शुरू हो गया है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए इस मेगा ब्लॉक को अनिवार्य बताया है। इस कार्य के कारण लखनऊ-कानपुर रूट पर 13 मई तक रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा।

रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि में 16 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। जबकि 27 ट्रेनों को डायवर्टेड रूट (बदले हुए मार्ग) से चलाया जाएगा। मेगा ब्लॉक के चलते कई महत्वपूर्ण इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनें लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगी।

आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी (12180/12179): यह ट्रेन अब केवल कानपुर सेंट्रल तक आएगी और यहीं से वापस आगरा के लिए शाम 5:25 बजे रवाना होगी।

झांसी-लखनऊ इंटरसिटी (11109/11110): वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) से आने वाली यह ट्रेन अब कानपुर तक ही संचालित होगी।

पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस (12103/12104): पुणे से आने वाली यह ट्रेन कानपुर में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी और शाम 6:00 बजे यहीं से पुणे के लिए प्रस्थान करेगी।

कासगंज-लखनऊ पैसेंजर: यह ट्रेन अब केवल कानपुर अनवरगंज स्टेशन तक ही चलेगी।

बदले हुए मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस (12004): यह ट्रेन 13 मई तक गाजियाबाद-मुरादाबाद रूट से चलेगी। ध्यान रहे कि यह ट्रेन अलीगढ़, टूंडला और कानपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

बरौनी/दरभंगा स्पेशल ट्रेनें: ये ट्रेनें बुढ़वल-सीतापुर सिटी-बरेली-मुरादाबाद रूट से संचालित होंगी।

बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ (20921): यह ट्रेन कासगंज-शाहजहांपुर-आलमनगर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी।

अन्य प्रभावित ट्रेनें: दिल्ली-बरौनी (02564), नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल (02570), उदयपुर सिटी-कामाख्या (19615), सूरत-मुजफ्फरपुर (19053), साबरमती-मुजफ्फरपुर (15270) के साथ-साथ यशवंतपुर-गोरखपुर, पनवेल-गोरखपुर और ओखा-गोरखपुर जैसी ट्रेनें भी डायवर्टेड रूट से चलेंगी।

व्यापार और छुट्टियां प्रभावित

लखनऊ और कानपुर के बीच दैनिक यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों, विशेषकर व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और छात्रों के लिए यह मेगा ब्लॉक बड़ी मुसीबत बन गया है। शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन का रूट बदलना और इंटरसिटी ट्रेनों की कटौती से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। गर्मी की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में पहले से ही भारी भीड़ है, ऐसे में ट्रेनों के निरस्त होने या रूट बदलने से आम जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। विकासखंड करंजकला क्षेत्र के लाडलेपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में गुरूवार को वाष िआयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया।मुख्य अतिथि के आगमन पर बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण उत्सवमय हो गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव होती है। उन्होंने अभिभावकों व शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन कराएं और विद्यालय की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकगण गांव के मजरे-मुजरों में जाकर लोगों से मिलें और नामांकन अभियान को सफल बनाएं। वार्षिक उत्सव के साथ-साथ 20 नए बच्चों का नामांकन भी किया गया, जो विद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। मुख्य अतिथि सुनील कुमार यादव उपस्थित रहे। संचालन सम्मानित अध्यापक अतुल प्रकाश यादव द्वारा किया गया। श्रीमती नीलम यादव दिनेश कुमार बृजेश कुमार पाण्डेय के साथ-साथ विंध्यवासिनी उपाध्याय, श्री प्रकाश मौर्य, शैलेंद्र पाल, मोहम्मद हाशिम, संदीप सिंह, श्रीपाल सहित समस्त हेडमास्टर, अध्यापकगण, गांव के अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

ऑफिस में जरूर बनाएं बाउंड्री, अपनाएं ये तरीके, मेंटल हेल्थ भी सुधरेगी

ऑफिस एक ऐसी जगह होती है जहां आप अपने दिन के कम से कम 9 घंटे बिताते हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ होती है और इसलिए ही जरूरी है कि आप अपने लिए कुछ लाइनें या बाउंड्रीज बनाएं ताकि आगे चलकर आपको वर्कप्लेस पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऑफिस में आपने भी कभी ये महसूस किया होगा कि कई बार हमें ये समझ नहीं आता है चीजें टॉक्सिक क्यों हो रही हैं या फिर सीनियर्स के साथ आपकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पाती है जितनी आपकी दूसरे साथी कलीग्स के साथ है। दरअसल हमारी खुद की गलतियां ही ऑफिस में परेशानियां आने की वजह बनती हैं। वर्कप्लेस पर गुड बिहेवियर वाली पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि काम के साथ ही इसका भी एनालिसिस किया जाता है। हालांकि आपको अपने लिए कुछ बाउंड्रीज (सीमाएं) तय करनी होंगी जो आपकी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए भी बहुत जरूरी है।

वर्कप्लेस पर भले ही आप अपने दिन का सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कलीग्स के साथ आपका रिश्ता प्रोफेशनल होता है और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में आपसे दोस्ती का रिश्ता रखते हैं। इसी के चलते हमें न सिर्फ प्रोफेशनली नुकसान हो जाता है, बल्कि इमोशनली भी हर्ट हो सकता है। इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए जान लें कि हमें ऑफिस में अपने व्यवहार को लेकर कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

पर्सनल लाइफ न करें ओवर शेयर

ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि बहुत ही संयमित होकर और सोच-समझकर बात करें। खासतौर पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में चीजों को ओवर शेयर करने से बचना चाहिए। इससे आपकी इमेज पर बुरा असर होता है। दरअसल लोग आपकी हर एक छोटी बात से जज कर सकते हैं। इसी के चलते कई बार आप किसी की गॉसिप की सब्जेक्ट भी बन सकते हैं।

सबके फ्रेंड न बनें

ऑफिस में आपको बिहेवियर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है तभी आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं बन सकता है। खुद को हर किसी से इमोशनली कनेक्ट न करें, बस प्रोफेशनली अपना रिश्ता सही रखें। बस कुछ ही लोग आपके दोस्त हो सकते हैं।

गॉसिप को अवॉइड करें

ऑफिस में किसी न किसी बात को लेकर गॉसिप्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन गॉसिप का हिस्सा न बनें। कई बार इन्हीं गॉसिप की वजह से आप फंस सकते हैं और आपकी इमेज खराब हो सकती है। दरअसल कई बार तो लोग गॉसिप करने के दौरान आपसे कुछ ऐसी बातें कहलवा देते हैं जो सीनियर्स के कानों तक भी पहुंच जाती हैं।

न कहना है बहुत जरूरी

किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होता है कि आपको अपना काम भी शिफ्ट में ही निपटाना है। जब तक कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त न हो तो खुद ही अपनी तरफ से मदद करने का ऑफर न करें। इसके अलावा अगर कोई बार-बार मदद मांगता है तो उसे विनम्रता के साथ मना करना सीखें।

अपने आइडिया न करें शेयर

ऑफिस में जरूरी है कि जिस तरह आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बाउंड्री तय करते हैं ठीक उसी तरह से आप ये सीमा भी तय करें कि किसके साथ आपका आइडिया शेयर करना सही है और किसके साथ नहीं। अगर आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है और फ्लो-फ्लो में आप अपने आइडिया भी शेयर कर देते हैं तो इससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर असर हो सकता है।

पार्टनर में ये आदतें ढूंढने की न करें गलती, रिश्ता होने लगता है कमजोर

रिश्ता कैसा भी हो इसमें उम्मीद रखने की आदत अमूमन हर किसी में होती है। लव रिलेशनशिप हो या मैरिड कपल...इनके बीच में भी अलग-अलग तरीकों से झगड़े होते हैं। वैसे पार्टनर में कुछ आदतों को तलाशने की गलती रिश्ते को खत्म करने की कगार तक ले जाती है। जानें इन आदतों के बारे में..

शादी या लव रिलेशनशिप में कपल के बीच झगड़ों का होना आम बात है। कहते हैं कि झगड़ा होना भी अच्छा है क्योंकि ये तरीका प्यार को बढ़ाता है। लेकिन कभी-कभी लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। यहां हम पार्टनर में कुछ आदतों को ढूंढने की गलती का जिक्र कर रहे हैं। रिश्ता कोई भी हो इसमें एक-दूसरे से उम्मीद लगाना नॉर्मल है। लेकिन इसके नाम पर रिश्ते को खराब करना कभी-कभी बहुत भारी पड़ जाता है। कई मामलों में कपल का रिश्ता टूटने के कगार पर तक पहुंच जाता है। कहीं आप भी तो अपने पार्टनर में कुछ आदतों को ढूंढने की भूल तो नहीं करते हैं।

इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं। रिलेशन में एक-दूसरे से उम्मीद लगाना अच्छा है लेकिन इसका वाजिब होना भी जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि पार्टनर में किन आदतों को ढूंढना रिश्ते के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

रिलेशनशिप में आने के रूल

लव रिलेशनशिप या शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो रिश्ते में आने से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे में खूबियां ढूंढते हैं। इसके बाद ही वे रिलेशनशिप में आते हैं। शादी तय होने की बात हो तो लड़की की तरफ से देखा जाता है कि लड़का अपने करियर में कैसा है। वहीं लड़के भी लड़कियों में जॉब करने से लेकर और भी कई खूबियां ढूंढते हैं। लव रिलेशनशिप वाले कपल शादी से पहले ही एक-दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ता चाहे लव हो या शादी का।। फिर भी लोगों को इसमें कुछ चीजों की बाउंड्री खुद से बनानी चाहिए।

पार्टनर में इन आदतों को ढूंढने की न करें गलती

उसका परफेक्ट होना

कुछ कपल्स के बीच में ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि एक पार्टनर परफेक्ट है तो वो दूसरे से भी उम्मीद करता है कि वो भी हर चीज में परफेक्शन रखें। हर मामले में उसका पार्टनर परफेक्शन के साथ डील करे। जरूरी नहीं है कि आपकी जैसी पर्सनालिटी है वैसी सामने वाली की भी हो। वो आपसे कम या ज्यादा हो सकता है। पार्टनर को परफेक्ट समझने या बनाने की आदत रिलेशनशिप में टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर सकती है।

हर बात पर सहमत हो जाए

पार्टनर आपकी सुनें और उस पर समहत हो जाए ये उसका अपना फैसला होना चाहिए।

रिलेशनशिप में कुछ लोग खासतौर पर पुरुष ऐसा मानते हैं कि उनकी पत्नी या पार्टनर हर बात पर उससे सहमत होनी चाहिए। हो सकता है कि आप गलत हो और आपका विरोध करके सामने वाला चीजों को खराब होने से बचा ले। इसलिए ये आदत बिल्कुल न डालें कि आपकी हर गलत या सही बात पर पार्टनर सहमत हो जाए।

बिना बोले समझ जाए

कुछ लोगों का नेचर डोमिनेटिंग होता है इसलिए वो सोचते कि उनका पार्टनर बिना कुछ बोले भी चीजें समझ जाए। इस तरह की डोमिनेशन वाली आदत आपके रिश्ते के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। हर टॉपिक पर अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और उसे अपनी राय रखने दें। वो आपके बोले बिना समझ जाए ऐसा हर बार संभव हो जरूरी नहीं है।

झगड़ा न करे

रिलेशन में झगड़ों का होना नॉर्मल है लेकिन आप अपने पार्टनर से ये उम्मीद करें कि वो किसी भी तरह से झगड़े ही नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सोच या आदत से भी रिश्ते पर खत्म होने का डर बना रहता है। ये एक उम्मीद है लेकिन इसकी भी लोगों को आदत पड़ जाती है। कहते हैं जहां तकरार है वहां प्यार भी ज्यादा होता

एक बार फिर चलन में आईं कैप्री, जानिए इस बॉटम वियर को स्टाइल करने के तरीके

गर्मियों में महिलाएं कैप्री पहनना पसंद करती हैं, जो मध्यम लंबाई वाली पैंट या जींस होती हैं। यह परिधान सालों बाद एक बार फिर चलन में आ गया है। इसे पहनने के बाद गर्मी महसूस नहीं होती है और एक स्टाइलिश लुक भी मिल जाता है। कैप्री को सही तरीके से स्टाइल करने पर आप हर मौके पर आकर्षक लग सकती हैं। चाहे वह ऑफिस हो या कोई खास अवसर, कैप्री को अलग-अलग तरीकों से पहना जा सकता है।

हाल्टर नेक टॉप के साथ पहनें

हाल्टर नेक इस साल की सबसे ट्रेंडी नेकलाइन है, जिसके टॉप कैप्री के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इस आउटफिट को पहनकर आपको एक स्टाइलिश और भीड़ से अलग लुक मिल जाएगा। जींस वाली कैप्री के साथ एकल रंग वाला हाल्टर नेक टॉप पेयर करें। इसके साथ आप पेंसिल या किटन हील पहन सकती हैं, जो आपको और भी आकर्षक लुक देंगी। लुक को पूरा करने के लिए एक सुंदर-सा शोल्डर बैग कैरी करें।

प्रिंटेड ब्लाउज के साथ मेल करें

अगर आप कुछ नया आजमाना चाहती हैं तो प्रिंटेड ब्लाउज के साथ कैप्री का मेल करना अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रिंटेड ब्लाउज आपके लुक में रंग भर देगा और आपको अलग दिखाएगा। आप फूलों वाले प्रिंट, पोल्का डॉट या ज्यामितीय डिजाइन वाले ब्लाउज चुन सकती हैं, जो गर्मियों की ताजगी को दर्शाते हैं। इसके साथ आप हल्के रंग की कैप्री पहन सकती हैं, जो आपके पूरे लुक को संतुलित बनाए रखेगी और आपको आकर्षक दिखाएगी।

ट्यूब टॉप के साथ स्टाइल करें

कैप्री को स्टाइल करने का सबसे पश्चिमी और खास तरीका होगा उसके साथ ट्यूब टॉप पहनना। यह आउटफिट गर्मी के लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपको जरा भी असुविधा महसूस नहीं होगी। कूल प्रिंट वाला ट्यूब टॉप पहनकर उसके साथ डेनिम जींस वाली कैप्री पेयर कर लें। इसके अलावा आप एकल रंग या सुंदर प्रिंट वाले ट्यूब टॉप के साथ हल्के रंग वाली कैप्री भी पहन सकती हैं। पैरों में फ्लैट चप्पल पहनकर लुक पूरा करें।

शर्ट के साथ लगेगी शानदार

अगर आप ऑफिस या कॉलेज में कैप्री पहनना चाहती हैं तो उसके ऊपर शर्ट पहन सकती हैं। यह स्टाइल खासतौर पर उन दिनों के लिए सही रहेगा, जब आप थोड़ा फॉर्मल लुक पाना चाह रही हों। आप नीली या सफेद रंग की शर्ट चुन सकती हैं और उसे गहरे रंग की कैप्री के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इस लुक के साथ किटन हील या लोफर्स पेयर करें, ताकि आपका पूरा लुक संतुलित और एलिगेंट नजर आए।

दुनिया में बजा भारत का डंका, इस ग्लोबल मामले में 56प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ बना नंबर वन

नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में भारत ने दुनिया भर में अपना परचम लहरा दिया है। भारत अब वैश्विक स्तर पर इस मामले में अग्रणी देश बन गया है। एबीएस क्लियरिंग-हाउस के जारी किए गए ताजा आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया भर में जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों में से 56 प्रतिशत से अधिक अकेले भारत ने जारी किए हैं। भारत ने कुल 6,311 वैश्विक प्रमाणपत्रों में से 3,561 आईआरसीसी जारी कर इस प्रोटोकॉल को लागू करने में बाकी सभी बड़े देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है।

फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देश भी छूटे पीछे

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले इस वैश्विक मंच यानी एबीएस क्लियरिंग-हाउस पर कुल 142 देश पंजीकृत हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से अब तक केवल 34 देशों ने ही आईआरसीसी जारी करने में कामयाबी हासिल की है। इस सूची में भारत पहले पायदान पर है, जिसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस है जिसने केवल 964 प्रमाणपत्र जारी किए हैं। इसके बाद स्पेन (320), अर्जेंटीना (257), पनामा (156) और केन्या (144) का नंबर आता है। यह शानदार आंकड़ा जैविक संसाधनों और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के पारदर्शी उपयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत है।

आखिर क्या है नागोया प्रोटोकॉल और आईआरसीसी?

नागोया प्रोटोकॉल के कड़े नियमों के तहत, उन सभी देशों को आईआरसीसी जारी करना अनिवार्य होता है जो अपने आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये प्रमाणपत्र इस बात का एक आधिकारिक और पुख्ता प्रमाण होते हैं कि संसाधनों के उपयोग के लिए पूर्व सूचित सहमति ले ली गई है और उपयोगकर्ता व प्रदाता के बीच आपसी शर्तों पर पूरी तरह से सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद इस पूरे विवरण को एबीएस क्लियरिंग-हाउस के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है, जिससे संसाधनों के उपयोग से लेकर उसके कमर्शियल एप्लीकेशन तक पूरी नजर रखी जा सके।

भारत ने कैसे हासिल किया यह बड़ा मुकाम?

वैश्विक स्तर पर भारत की यह नंबर वन पोजीशन जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत बनाए गए इसके प्रभावी ढांचे को दर्शाती है। देश में इसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य बोर्डों और स्थानीय स्तर पर प्रबंधन समितियों के जरिए शानदार तरीके से लागू किया गया है। भारत की इसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया और मजबूत तंत्र ने न सिर्फ आवेदनों को तेजी से निपटाने में मदद की है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया है। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि वैश्विक पर्यावरण समझौतों और जैव विविधता संरक्षण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाती है।

पेट्रोल पंप पर सिर्फ 'जीरो' देखकर हो रहे हैं खुश? ऐसे कट रही है आपकी जेब

जब भी हम अपनी कार या बाइक में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो वहां मौजूद कर्मचारी सबसे पहले हमें मीटर में 'जीरो' चेक करने के लिए कहता है। हम भी '0' देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे वाहन में पूरा फ्यूल भर गया है और पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां आपकी नजरें सिर्फ जीरो देखने में अटकी रहती हैं, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप वाले आपकी जेब काटने का बड़ा खेल कर देते हैं और आपको इसकी भनक तक नहीं लगती। आइए आपको बताते हैं कि आखिर यह खेल कैसे होता है और अगली बार पेट्रोल पंप जाने पर आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए।

सिर्फ 'जीरो' नहीं, इस मीटर पर भी रखनी होगी पैनी नजर

पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को चूना लगाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी आए दिन इससे जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें पेट्रोल पंप कर्मचारी खुद इस धांधली की सच्चाई बताते नजर आते हैं। दरअसल, असली खेल जीरो के मीटर में नहीं, बल्कि डेंसिटी (ष्ठद्गठ्ठह्यद्बह्ल4) के आंकड़े में होता है। आपने भी गौर किया होगा कि पेट्रोल पंप कर्मी आपको हमेशा जीरो देखने के लिए तो कहता है, लेकिन कभी डेंसिटी मीटर पर नजर डालने के लिए नहीं बोलता। डेंसिटी मीटर पर प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों में हेरफेर करके ही ग्राहक को खुली आंखों के सामने ठगा जाता है।

आखिर क्या होता है डेंसिटी मीटर और क्यों है यह जरूरी?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डेंसिटी मीटर होता क्या है। यह आपके वाहन में डाले जाने वाले पेट्रोल या डीजल की शुद्धता का सबसे बड़ा पैमाना होता है। यह बताता है कि जो फ्यूल आप डलवा रहे हैं वह कितना शुद्ध है या फिर उसमें मिलावट करके आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकार की तरफ से इसके लिए मानक तय किए गए हैं। पेट्रोल की डेंसिटी 720 से 775 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि डीजल के मामले में यह डेंसिटी 810 से 845 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित की गई है। अगर आपके फ्यूल की डेंसिटी इस दायरे में नहीं है, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी में मिलावटी तेल डाला जा रहा है।

मीटर की जंपिंग पर भी रखें खास ध्यान

डेंसिटी मीटर के अलावा जीरो वाले मीटर पर भी आपको एक खास चीज नोटिस करनी चाहिए। फ्यूल भरना शुरू होते ही अगर मीटर 0 से बढ़कर सीधे 10 पर पहुंच जाता है, तो समझ लीजिए कि उस मशीन में गड़बड़ी है और आपको चूना लगाया जा रहा है। सही मशीन में मीटर हमेशा 0 से शुरू होकर 3, 4, 5 जैसे छोटे नंबरों के साथ आगे बढ़ता है। मिलावटी तेल से न सिर्फ आपकी जेब कटती है, बल्कि आपकी महंगी गाड़ी का इंजन भी समय से पहले खराब हो सकता है।

पैनिक बायिंग के इस दौर में धोखाधड़ी से खुद को बचाएं

गौरतलब है कि इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भीषण युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ह्लह्म्ड्डद्बह्ल शद्घ ॥शह्म्द्वह्ल5) बंद होने के कारण दुनियाभर में तेल का गहरा संकट पैदा हो गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। भारत में भी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और पंजाब तक के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ और पैनिक बायिंग देखने को मिल रही है। हालांकि, सरकार और तेल कंपनियों ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घबराहट में की जाने वाली इस खरीदारी के दौरान फ्रॉड के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसे में पेट्रोल भराते समय ये सावधानियां अपनाना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

केंद्र ने छोटी बचत योजनाओं में अप्रैल-जून के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को छोटी बचत योजनाओं पर अप्रैल-जून अवधि के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखने का ऐलान किया है। इस फैसले से पीपीएफ, एनएससी और केवीपी जैसे योजनाओं पर ब्याज दर आने वाली तिमाही में यथावत बनी रहेगी।

यह लगातार आठवीं तिमाही है, जब केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को स्थिर रखा है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा,वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (1 अप्रैल, 2026 से शुरू होकर 30 जून, 2026 को समाप्त) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026) के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी।

अधिसूचना के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत और किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत रहेगी। वहीं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर 4 प्रतिशत और तीन वर्ष के टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत पर बरकरार रहेगी।

अप्रैल-जून अवधि के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) पर ब्याज दर 7.7 प्रतिशत रहेगी। मंथली इनकम स्कीम पर निवेशकों को 7.4 प्रतिशत की ब्याज मिलेगी।

केंद्र सरकार छोटी बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरें हर तिमाही के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करती है।

कई छोटी बचत योजनाओं जैसे एसएसवाई, पीपीएफ और एनएससी में इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स रिजीम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है।

ज्यादातर छोटे बजट योजनाओं को पोस्ट ऑफिस और बैंकों की मदद से खरीदा जा सकता है। इन्हें एक रिस्क फ्री एसेट माना जाता है, क्योंकि इनमें भारत सरकार की गारंटी होती है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग बचत के लिए छोटी बचत योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं।

मुज्तबा खामेनेई के वो 5 फैसले, जिससे जंग में घुटनों पर आ गया अमेरिकाहोर्मुज से हटा पीछे

वॉशिंगटन, एजेंसी। 28 फरवरी को ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद युद्ध में तेहरान के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे। अमेरिका और इजराइल ने तुरंत जंग खत्म कर ईरान में नए नेता तलाशने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान भी दिया था, जिसमें उनका कहना था कि मैंने अपने मन में नेता का चयन कर लिया है। जल्द ही आप सबको बताया जाएगा, लेकिन युद्ध के 34वें दिन स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

अमेरिका अब ईरान को आजाद नहीं कराना चाहता है। वो बमबारी के जरिए ईरान को पाषाण काल में भेजना चाहता है। यह इसलिए, क्योंकि जंग में ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। ट्रंप के धुर विरोधी नेता और और कैलिफॉर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम का कहना है कि ट्रंप के पास युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पिता की हत्या के करीब 10 दिन बाद सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए मुज्तबा ने अपने 5 फैसले से दुनिया के सुपरपावर को सरेंडर मोड में ला दिया है। कैसे, आइए विस्तार से समझते हैं

घुटनों पर कैसे आ गया अमेरिका?

1। युद्ध के 34वें दिन डोनाल्ड ट्रंप को देश के सामने आना पड़ा है। देश को संबोधित करते हुए ट्रंप ने युद्ध को जरूरी बताया है। ट्रंप ने लोगों से कहा कि युद्ध में अगर हम नहीं उतरते तो भविष्य सुरक्षित नहीं था।

2। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान में होर्मुज में एंटर नहीं करने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। उधर, समझौते के तहत जेडी वेंस ने सबसे पहले होर्मुज खोलने की बात कही है।

3। ट्रंप ने ईरान में अब सिर्फ 3 हफ्ते तक युद्ध करने की बात कही है। पहले वे तख्तापलट के मकसद से ईरान में आए थे। ट्रंप ने अब ईरान को पाषाण युग में भेजने की बात कही है। इसे जानकार ट्रंप की खिज बता रहे हैं।

मुज्तबा के 5 फैसले को पढ़िए

1। सुप्रीम लीडर मुज्तबा ने 6 दिन के जंग में ही होर्मुज बंद करने का फैसला कर लिया। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तब 12 दिन के जंग में भी होर्मुज को ब्लॉक नहीं किया गया था। इस बार मुज्तबा ने पहले ही होर्मुज में नाकेबंदी कर दी, जिससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई।

2। मुज्तबा ने इस बार वीडियो बयान जारी नहीं किया। सुप्रीम लीडर की तरफ से सिर्फ लिखित बयान सामने आए। दरअसल, मुज्तबा जानते थे कि अगर वे वीडियो जारी करेंगे, तो उनके लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है। इजराइल और अमेरिका के उकसाने पर भी उन्होंने सिर्फ लिखित आदेश जारी किए।

3। ईरान में सेना को टुकड़ों में बांट दिया गया है। छोटे-छोटे स्तर पर भी सेना के जवान खुद हमले को लेकर फैसला कर सकते हैं। यह इसलिए किया गया है कि ताकि अमेरिका तुरंत ईरान पर कब्जा न कर सके। ईरान ने इस फैसले से जंग को लंबा खिंच दिया है। यह अमेरिका के लिए सिरदर्द बना हुआ है।

4। शुरुआत में ब्रिटेन ने जंग में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को चागोस द्वीप पर स्थित बेस को देने का फैसला किया था। ईरान ने वहां पर अटैक कर दिया। इसके जरिए ईरान ने ब्रिटेन को यह संदेश दिया कि हम दूर तक भी लड़ाई कर सकते हैं। ईरान के पास ब्रिटेन पर हमला करने वालें मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके बाद ब्रिटेन ने जंग से खुद को दूर कर लिया।

5। ईरान का कम्युनिकेशन सेटअप बेहतरीन तरीके से व्यवस्थित किया गया है। सभी दूतावास को एक्टिव किया गया है। आधिकारिक बयान तुरंत जारी किए जा रहे हैं, जिससे युद्ध में अमेरिका और इजराइल का प्रोपगंडा नहीं चल पा रहा है।

अंतरिक्ष में टॉयलेट का जिक्र! आर्टेमिस-2 में गए यात्रियों के कमांडर ने पहले संदेश में क्या कहा?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एसएलएस (SLS) रॉकेट ने 'इंटीग्रिटी' नाम के ओरियन कैप्सूल को अंतरिक्ष में पहुंचाया। भारतीय समय के अनुसार यह लॉन्चिंग गुरुवार सुबह 4:05 बजे हुई। इस मिशन के साथ ही इंसान करीब 54 साल बाद एक बार फिर चांद की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस मिशन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर नासा की टीम और अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई दी है। उन्होंने इस लॉन्च को अद्भुत बताया। इस ऐतिहासिक मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। टीम की कमान रीड वाइसमैन संभाल रहे हैं। उनके साथ पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैनसेन यात्रा कर रहे हैं।

ट्रंप नाटो से नाराज : ईरान में जंग के बीच विदेश मंत्री रुबियो की पुरानी पोस्ट वायरल क्यों

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का दो साल पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट फिर से चर्चा में आ गया है। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पास नाटो (NATO) से अकेले बाहर निकलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह मामला तब दोबारा उठा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म होने के बाद वह नाटो में अमेरिका की भूमिका पर फिर से विचार करेंगे।

दिसंबर 2023 में रुबियो फ्लोरिडा से सीनेटर थे। तब उन्होंने एक्स पर लिखा था, 'किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को सीनेट की मंजूरी के बिना नाटो से हटने का अधिकार नहीं होना चाहिए।' उस समय रुबियो ने एक कानून का समर्थन किया था। यह कानून किसी भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की सहमति के बिना इस ऐतिहासिक सैन्य गठबंधन से बाहर निकलने से रोकता है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हितों और लोकतांत्रिक सहयोगियों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम बताया था।

पुराना पोस्ट हुई वायरल

बुधवार को यह पुराना पोस्ट फिर से वायरल हो गया और इसे 23 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। इस पर सीनेट में अल्पमत के नेता चक शूमर ने भी अपनी बात रखी। शूमर ने कहा कि सीनेट नाटो छोड़ने और अपने सहयोगियों का साथ छोड़ने के पक्ष में वोट नहीं देगी। उन्होंने रुबियो को उस कानून के लिए धन्यवाद दिया जिसके तहत नाटो छोड़ने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। शूमर ने कहा कि यह कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसा फैसला न ले सके।

क्या बोले रुबियो?

मंगलवार को एक टीवी कार्यक्रम में रुबियो ने अपनी पुरानी स्थिति पर बात की। उन्होंने माना कि पहले वह नाटो को अमेरिका की ताकत बढ़ाने का एक अच्छा जरिया मानते थे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि नाटो एकतरफा रास्ता बन गया है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका को सैन्य कार्रवाई में मदद की जरूरत है, तब कई वैश्विक नेता पीछे हट रहे हैं। खबरों के अनुसार, इटली और स्पेन ने अमेरिकी विमानों को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। फ्रांस और स्पेन ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। रुबियो ने सवाल उठाया कि अगर जरूरत के समय इन ठिकानों का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, तो वहां अरबों डॉलर और अमेरिकी सेना रखने का क्या फायदा?

अपने ही घर में घिरे ट्रंप : डेमोक्रेटिक सांसदों ने यूएस के भविष्य पर उठाए सवाल, पूछा- ईरान से जंग कब होगी खत्म

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान नीति पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आगे चलकर इस युद्ध की मानवीय, आर्थिक और भू-राजनीतिक कीमत बहुत भारी पड़ रही है। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले सांसदों ने एक साझा बयान जारी कर अपनी चिंताएं जाहिर की।

सांसद ग्रेगरी मीक्स, एडम स्मिथ और जिम हाइम्स ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ यह युद्ध शुरू किया था। इसे शुरू हुए एक महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ट्रंप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। सांसदों का तर्क है कि इस सैन्य कार्रवाई से ईरान के शासन में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है। ईरान अब भी परमाणु कार्यक्रम चलाने, मिसाइलें बनाने और आतंकी समूहों की मदद करने में सक्षम है। इसके अलावा, ट्रंप ईरान के आम लोगों को भी कोई राहत नहीं दे पाए हैं।

नुकसान पर क्या बोले सांसदों

सांसदों ने इस युद्ध में हुए जान-माल के मानवीय और भौतिक नुकसान को उजागर करते हुए बयान में आगे कहा, अब तक 13 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। युद्ध में अरबों डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण या तो बर्बाद हो गए हैं या उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है।

मानवीय नुकसान का जिक्र करते हुए सांसदों ने कहा कि हजारों ईरानी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा स्कूली छात्राएं भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप की इस विनाशकारी कार्रवाई की वजह से बहुत से लोग अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और कट्टरपंथ बढ़ रहा है।

अर्थव्यवस्था और सहयोगियों पर असर

बयान में कहा गया कि इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल, खाद और हीलियम जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई कम हो गई है। इससे अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रंप ने अपने पुराने और वफादार सहयोगियों का अपमान किया, उन पर दबाव डाला है और उन्हें नीचा दिखाया है। इसी वजह से अब कई मित्र देश इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने से मना कर रहे हैं।

कूटनीतिक समाधान की अपील

डेमोक्रेटिक सांसदों ने मांग की है कि ट्रंप देश को बताएं कि यह युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वह तुरंत ईरान के साथ युद्धविराम पर बातचीत शुरू करें। सांसदों के अनुसार, इस विनाशकारी युद्ध को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कूटनीतिक समाधान नहीं निकाला गया, तो अमेरिका एक और कभी न खत्म होने वाले युद्ध में फंस जाएगा, जिसके परिणाम और भी भयानक होंगे।

पाक की ना'पाक' साजिश : भारत के रक्षा और वित्तीय ढांचे पर साइबर हमलों की योजना, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के महत्वपूर्ण रक्षा और वित्तीय ढांचे को निशाना बनाने के लिए बहुस्तरीय साइबर हमलों की योजना बना रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में आईएसआई अधिकारियों ने कई बैठकें कर इन हमलों की रणनीति तैयार की है, जिनका उद्देश्य भारत के अहम संस्थानों को ठप करना और संवेदनशील जानकारी हासिल करना है। अधिकारियों के मुताबिक, इन हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान साइबर फोर्स को सक्रिय किया गया है। साथ ही विभिन्न हैकर समूहों को भी सक्रिय किया गया है, जिससे हाल के दिनों में गतिविधियों में तेजी देखी गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के 2025 के आकलन में भी 2026 में पाकिस्तान से जुड़े साइबर हमलों को सबसे बड़ा खतरा बताया गया था। सूत्रों के अनुसार, आईएसआई साइबर समूह HOAX1337 और नेशनल साइबर क्रू जैसे समूहों का इस्तेमाल कर भारतीय परिसंपत्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रही है। इन समूहों का पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। खासतौर पर रक्षा क्षेत्र को प्राथमिक लक्ष्य बनाया गया है, जहां सिस्टम को बाधित करने के साथ-साथ गोपनीय सूचनाएं चुराने की कोशिश की खुफिया एजेंसियों ने यह भी बताया कि आईएसआई का जासूसी नेटवर्क भारत में सक्रिय है, जो रक्षा क्षेत्र के अलावा रेलवे स्टेशनों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटा रहा है। गाजियाबाद पुलिस की जांच में सामने आया कि कुछ लोगों ने सोलर पावर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान में बैठे संचालकों को लाइव फीड भेजी।

अफवाहों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश

अधिकारियों के अनुसार, यह साजिश दोहरे तरीके से संचालित होगी। एक तरफ साइबर हमलों के जरिए रक्षा ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी। वहीं, दूसरी ओर दुष्प्रचार अभियान चलाकर भ्रम फैलाया जाएगा। चुनावी माहौल को देखते हुए ऐसे अभियानों में तेजी आने की आशंका जताई गई है।

इसके अलावा फर्जी कॉल और संदेशों के जरिए तेल और एलपीजी की कीमतों को लेकर अफवाह फैलाने की योजना भी सामने आई है। इसका मकसद आम लोगों में घबराहट पैदा करना और बाजार में कालाबाजारी बढ़ाना है। शिक्षा और विमानन क्षेत्रों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अफवाह से तुरंत असर पड़ता है।

पाकिस्तान खर्चकर रहा मोटी रकम

सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं का लगातार खंडन और तथ्य जांच की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि आईएसआई इन गतिविधियों पर भारी धनराशि खर्च कर रही है और भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है।

उधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर पश्चिमी देश परेशान, इधर दिल्ली में भारत और रूस के बीच हो रहीं अहम डील

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर परेशान हैं। वहां उनके कई जहाज फंसे हैं। एक ओर जहां पश्चिमी देश ईरान के कदम से टेंशन में हैं तो वहीं इधर नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच अहम डील होने जा रही है। ये समझौते रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव की नई दिल्ली यात्रा के दौरान होने जा रही है। मांतुरोव रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और कई अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर उच्च-स्तरीय चर्चाओं के लिए गुरुवार सुबह नई दिल्ली पहुंचे।

अपनी यात्रा के दौरान वह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ वार्ता करेंगे और अन्य द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरे का मुख्य जोर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर रहने की उम्मीद है। विशेष रूप से सुरक्षा और

रक्षा सहयोग के क्षेत्रों में।

डोभाल-सीतारमण से भी करेंगे मुलाकात

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मांतुरोव अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि चर्चाएं रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर केंद्रित रहेंगी। मांतुरोव के दौरे से पहले, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने 30 मार्च को नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर

दोनों पक्षों ने पिछले साल दिसंबर में नई दिल्ली में हुए भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को लागू करने में हुई प्रगति का भी जायजा लिया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य ज़ोर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर था।

ट्रंप की कोशिश नाकाम

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। उन्होंने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। इस कदम का मकसद भारत को रूसी ऊर्जा क्षेत्र से दूर करना था, जिससे अमेरिकी नीति निर्माताओं के अनुसार, यूक्रेन संकट को सुलझाने में मदद मिलती।

बॉलीवुड हसीनाएं, जिनकी एक्टिंग के दम पर फिल्में हुईं सुपरहिट

महिलाओं ने बॉलीवुड में अपनी काबिलियत को बखूबी दिखाया है। बॉलीवुड की कई ऐसी हीरोइनें हैं, जिन्होंने फिल्म बिना किसी हीरो के अपने बूते हिट करवाई है। कहने का मतलब साफ है कि अगर ऐसा समझा जाए कि सिर्फ हीरो के दम पर ही फिल्में चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर फिल्म में हीरोइन का रोल दमदार हो, तो इसका कमाल दिखना तय है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन हीरोइनों की बात करेंगे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को हिट और सुपरहिट की श्रेणी तक पहुंचाया।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट की बात करें, तो उनकी फिल्में 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'राजी' ऐसी फिल्में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ही फिल्मों में आलिया का लीड रोल था। आलिया का अभिनय ही था कि ये दोनों फिल्में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुईं। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के लिए तो आलिया को नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने 200 करोड रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। कम बजट में बनी 'राजी' ने भी 100 करोड़ से ज्यादा कमाए।

सोनम कपूर

जब महिलाओं पर आधारित फिल्मों की बात करें, तो ऐसे में सोनम कपूर का और उनकी फिल्म 'नीरजा' का जिक्र जरूरी हो जाता है। सोनम कपूर ने इस फिल्म में अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भनोट का रोल निभाया था। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह एयर होस्टेस ने अपनी जान की बाजी लगाकर विमान में मौजूद यात्रियों को बचाया था। सोनम ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाली दी थी।

कंगना रणौत

विकास बहल के डायरेक्शन में बनाई गई कंगना रणौत की फिल्म 'कवीन' का जादू ऐसा चला कि फिल्म ने खूब तारीफ पाई। कंगना का शानदार अभिनय फिल्म को कामयाब बनाने के पीछे की एक बड़ वजह रहा। इस बेहतरीन फिल्म के बाद तो कंगना को फैंस ने बॉलीवुड क्वीन नाम ही दे दिया। रानी मेहरा के किरदार ने दर्शकों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

रानी मुखर्जी

फिल्म 'मर्दानी' में रानी मुखर्जी के एक्शन सीन्स का ऐसा जलवा दिखा कि फैंस को भा गया। सीन्स के साथ उनका एक-एक डायलॉग ऐसा था जिसे एक बार सुनो, तो लंबे समय तक आपके कानों में गूंज रहेगी। एक डायलॉग आपको भी याद दिलवा दें-'जिस दुनिया में मां बहने रिश्ते नहीं गाली हैं, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोडूंगी।' रानी का कमाल ही था कि फिल्म को हिट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

विद्या बालन

विद्या बालन की 'डर्टी पिक्चर' की बात करें, तो फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग ने ऐसा कमाल किया कि बहुत ही कम बजट में बनने के बावजूद इसने खूब अच्छा प्रदर्शन किया। विद्या ने अपना बोल्ड अवतार दिल खोलकर दिखाया। फिल्म का पहला पोस्टर आते ही विद्या की बोल्ड इमेज की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही विद्या ने अपनी जोरदार एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया।

कालीदास 2 को मिला यू/ए सर्टिफिकेट, 3 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी थ्रिलर फिल्म

फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी हिट फिल्म का सीक्वल आता है, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है कालीदास 2, जो अपने पहले पार्ट की सफलता के बाद अब दर्शकों के बीच वापसी करने जा रही है। रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है और अब इसे लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने इस फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट दे दिया है। इसका मतलब है कि फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है और इसे परिवार के साथ देखा जा सकता है, हालांकि बच्चों के लिए अभिभावकों की सलाह जरूरी होगी। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी और साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया। यह फिल्म 3 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।

फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में एक और खास अपडेट शेयर किया था, जिसमें अभिनेता किशोर का फर्स्ट लुक सामने आया था। इस फिल्म में वह पांड्या नाम के किरदार में नजर आएंगे। पोस्टर में उनका लुक काफी खतरनाक और रहस्यमयी दिखाया गया है। मेकर्स ने उनके किरदार को रॉ, रफ और अनप्रिडिक्टेबल करार दिया।

यह फिल्म सालों पहले आई सुपरहिट फिल्म कालीदास का दूसरा पार्ट है। इसे के.सेंथिल और डॉ. एन योगेश्वरन ने प्रोड्यूस किया है। खास बात यह है कि इस फिल्म को भी सेंथिल ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले पार्ट को भी बनाया था। ऐसे में दर्शकों को उम्मीद है कि यह फिल्म भी उतनी ही दमदार होगी।

फिल्म में भरत और अजय कार्थी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा, भवानी श्री, संगीता और टीएम कार्तिक समेत कई कलाकार भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। संगीता लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, जो दर्शकों के लिए एक अलग ही रोमांच लाएगा।

फिल्म के टीजर की बात करें तो, यह डरावने और भावनात्मक सीन से भरपूर है। टीजर में देखा जा सकता है कि भरत एक पुलिस अधिकारी के किरदार में हैं; उनको एक महिला का फोन आता है, जो काफी डरी हुई है और उनसे मदद की गुहार लगा रही है।

टीजर में एक वॉयसओवर भी सुनाई देता है, इसमें कहा गया है कि हर अपराध की सजा होती है, लेकिन कुछ मामलों में सजा किसी बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अलग तरीके से मिलती है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com